A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 17 जनवरी, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 137, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

विश्व व्यापार के लिए जरूरी इयू-भारत समझौता अपने आखिरी चरण में

केशव पद्मनाभन

लंबे समय से बातचीत में रहे भारत-यूरोपीय संघ (इयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर 27 जनवरी को दोनों साझेदारों के बीच होने वाले 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर होने की तैयारी है। यूरोपीय संघ के नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और काउंसिल अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा–25 से 27 जनवरी के बीच भारत आएंगे। भारत के लिए यह एफटीए 18 ट्रिलियन यूरो के बाज़ार तक बेहतर पहुंच देगा, जहां 40 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं इयू के 27 सदस्य देशों के लिए भारत के साथ व्यापार समझौते का मतलब होगा कम टैरिफ और दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार–1.4 अरब लोगों और तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था–तक बेहतर पहुंच।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत के व्यापार आंकड़ों पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'पिछले तीन महीनों से हम इयू के साथ बातचीत के आखिरी और सबसे कठिन चरण में थे। हमने 24 में से 20 अध्याय पूरे कर लिए हैं। कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं और उन पर वर्चुअल बातचीत चल रही है। हम आमने-सामने मिलने की भी योजना बना रहे हैं।'

सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि 'दोनों पक्षों के संवेदनशील कृषि मुद्दे बातचीत के दायरे से बाहर हैं।' जबकि नई दिल्ली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (सीबीएएम) जैसे विवादित मुद्दों पर छूट (कार्व-आउट) की मांग जारी रखे हुए है। सीबीएएम 1 जनवरी से लागू हो चुका है और इसमें स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर शामिल होंगे। आगे चलकर और सेक्टर भी जोड़े जाने की उम्मीद है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया, 'सीबीएएम एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। यह समझौता पर्यावरण, टिकाऊपन और श्रम जैसे गैर-कोर व्यापार क्षेत्रों को भी कवर करता है। इयू चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में खास प्रतिबद्धताएं करे। भारत इसके लिए तैयार नहीं है और इन अध्यायों को 'बेस्ट एंडेवर' क्लॉज़ तक सीमित रखना चाहता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'सीबीएएम एक टैरिफ बाधा है। एफटीए के बाद, अगर सीबीएएम का समाधान नहीं होता, तो यूरोपीय सामान भारत में ज़ीरो टैरिफ पर आएंगे, जबकि हमारे सामान सीबीएएम के कारण बाधाओं का सामना करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि अभी ईयू का सीबीएएम छह उत्पाद क्षेत्रों को कवर करता है, लेकिन आने वाले वर्षों में इयू सभी औद्योगिक उत्पादों को इसके तहत लाएगा। इसलिए अगर सीबीएएम का समाधान किए बिना एफटीए किया गया, तो यह समझौता असंतुलित होगा।'

हालांकि, दोनों पक्षों में इस समझौते को आगे बढ़ाने की राजनीतिक इच्छा है। जैसा कि एक यूरोपीय राजनयिक ने स्थिति को बताया–व्यापार समझौते इयू की 'लव लैंग्वेज' हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छह मूल सदस्य देशों–फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड–के बीच व्यापार आसान करने के लिए बने इस संगठन का दायरा अब काफी बढ़ चुका है।

आज इयू एक एकल बाज़ार है, जहां सदस्य देशों के भीतर सामान, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही है। हालांकि, व्यापार को केंद्र में रखने वाला इयू अपने सदस्य देशों को तीसरे देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की अनुमति नहीं देता। इसी वजह से नई दिल्ली और ब्रसेल्स को मिलकर यह समझौता तय करना पड़ता है।

जब सभी 27 सदस्य देशों के साथ निर्यात और आयात को जोड़ा जाता है, तो इयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों के लिए यह समझौता लगभग दो दशक से बन रहा है। व्यापार समझौते के लिए बातचीत का पहला दौर 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। फिर 2022 में बातचीत दोबारा शुरू हुई।

श्रीवास्तव ने बताया, 'इयू को भारत का माल निर्यात लगभग 76 अरब डॉलर (वित्त वर्ष 2025 में) है, और हम उनसे जितना आयात करते हैं (60.7 अरब डॉलर), उससे ज़्यादा निर्यात करते हैं। ज़्यादातर विकसित देशों में आयात शुल्क का एक पैटर्न होता है। वे कुल मिलाकर टैरिफ कम रखते हैं, लेकिन श्रम-प्रधान सामान–जो विकासशील देशों के मुख्य उत्पाद होते हैं–उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं।'

अब तक की हुई बातचीत के दौरान स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य मानकों (एसपीएस) से जुड़े अध्याय को पूरा कर लिया गया और ऑटोमोबाइल तथा दवाइयों जैसे मुद्दों पर समझौते के पैकेज चिन्हित किए गए। निवेश से जुड़े अध्याय में काफी बड़े मतभेद सामने आए। व्यापार समझौते में दी जाने वाली छूटों को लेकर कोई सहमति या समझौता नहीं हो पाया। वहीं, भारत पिछले तीन महीनों से पूंजी की आवाजाही को लेकर इयू के समझौता पैकेज पर विचार कर रहा है।

हालांकि, वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ घटाने और 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' को लेकर मतभेद बने रहे, जिन पर सत्रों के बीच लगातार चर्चा होती रही है। खास बात यह है कि भारत ने 2025 में ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड जैसे अन्य विकसित देशों के साथ बातचीत पूरी कर ली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मेज़ पर कई तरह के समझौते मौजूद हैं। डेयरी सेक्टर को इस समझौते से बाहर रखे जाने की संभावना है। यह कृषि उत्पादों पर बातचीत के साथ-साथ भारत की 'रेड लाइन' का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर, डेयरी को छूट देने के मुद्दे ने इयू के भीतर भी आंतरिक सवाल खड़े किए हैं।

फिर भी, भारत और इयू दोनों के लिए यह समझौता ज़रूरी माना जा रहा है। इयू के लिए भारत के साथ समझौता करने से वह आधुनिक वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रमुख निर्माताओं में बना रह सकेगा। यह व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा व्यापार के प्रवाह को दोबारा तय करने की कोशिशों के बाद काफ़ी दबाव में आ गई है। इसके अलावा, चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत ने उसे अपने पक्ष में व्यापार व्यवस्था को ढालने का मौका दिया है, जिससे इयू खुद को असमंजस में पाता है।

यूरोपीय आयोग द्वारा लगभग एक दशक पहले–2018 में–जारी एक नीति दस्तावेज़ में बताया गया था कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में इयू की कुल हिस्सेदारी 2000 में 27 प्रतिशत से घटकर 2014 में लगभग 16 प्रतिशत रह गई, और हाई-टेक वैल्यू चेन में यह गिरावट और ज़्यादा साफ दिखती है। इयू की प्रतिस्पर्धात्मकता की काफ़ी आलोचना होती रही है। इन सभी बातों के चलते यह समझौता अब आखिरी चरण में पहुंच गया है और उम्मीद है कि मुख्य बातचीत पूरी होने के बाद भी अहम मतभेदों पर बातचीत जारी रहेगी।

(द प्रिंट में प्रकाशित आलेख के संपादित अंश साभार)

शरद की सुबह

न तेरे नाम का कूचा न
मेरे नाम का शहर
कहीं अल्लाह की बस्ती है
कहीं राम का शहर

जिंदगी जह्दे मुसलसल के
सिवा कुछ भी नहीं
यार मैंने भी बसाया नहीं
आराम का शहर

कितने खामोश मोहल्ले
कई उतरे चेहरे
तुम मेरे जाम में देखो तो
मेरे जाम का शहर

जंग है भूख है
अफ्लास है बेकारी है
जिस जगह जाऊँ मिले है
दिले नाकाम का शहर

अब भी जलते हैं उम्मीदों के
दिए गम के चराग
तूने देखा नहीं अब तक
दिले बदनाम का शहर।

– शमीम फरहत

भाजपा की करिश्माई जीत, ठाकरे का 'किला' ढहा

● 28 साल बाद बीएमसी से आउट हुई ठाकरे की पार्टी ● पूरे महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की रही बम-बम

● 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी और सहयोगी छाए ● मुंबई-नागपुर-पुणे फतह, लातूर-चंद्रपुर में कांग्रेस को बहुमत

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। 29 में 23 नगर निगमों बीजेपी गठबंधन ने फतह हासिल कर ली है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। सभी निगमों में सबसे अहम बृहन्मुंबई महानगरपालिका है। यहां भाजपा और शिवसेना गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। कोल्हापुर में पहले कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन अब बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुकी है। संभाजीनगर में भी बीजेपी ने किला फतह कर लिया है। लातूर और चंद्रपुर में कांग्रेस को जीत मिली है। राज्य में नगर निगम चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा- आज जश्न का दिन है। महाराष्ट्र में सभी नगर समितियों और नगर निगमों के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों, उनके राष्ट्रवाद और विकसित भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत साफ दिखाती है कि लोग पाकिस्तान की सेना के धुन पर नाचने वालों को अपने वोटों से सबक सिखा रहे हैं। यह नतीजा राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन को मिली बढ़त पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि- आप सभी ने देखा कि आज बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। यह दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

गालीबाजी, लुंगी-पुंगी, कुछ नहीं आया काम

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति को नया संदेश गया है। नफरती पॉलिटिक्स हीरो रहे राज ठाकरे निकाय चुनाव में खत्म हो गए हैं। मनसे मुंबई महानगरपालिका में तीन से चार सीटें जीतती दिख रही है। मराठी अस्मिता के नाम पर गालीबाजी और लुंगी–पुंगी करने वाले राज ठाकरे के नफरती पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके चक्कर में उद्धव ठाकरे के हाथ भी जल गए हैं। बीएमसी की सत्ता 30 साल बात उद्धव ठाकरे के हाथों से जा रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में नफरती पॉलिटिक्स को लेकर ही रही है।

अजित पवार के दोनों गढ़ में खिला कमल

महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बीजेपी की लहर सामने आई है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। अजित पवार की पार्टी ने महायुति को छोड़कर मुंबई में जहां अकेले चुनाव लड़ा था तो वहीं पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ पुणे, पिंपरी चिंचवड में वापसी के लिए चाचा (शरद पवार) की अगुवाई वाली एनसीपी से हाथ मिलाया था। इसके बाद सुप्रिया सुले और अजित पवार एक मंच पर सामने आए थे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड में खूब चुनाव प्रचार किया था, लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों स्थानों पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी ह तो वहीं दूसरी एनसीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। अजित पवार ने 29 महानगरपालिका के चुनावों में सबसे ज्यादा जोर एशिया की सबसे अमीर मानी जाने वाली पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका के लिए लगाया था। चुनाव प्रचार में उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार तक के आरोप भी लगाए थे, लेकिन पिंपरी चिंचवपड में अजित पवार की पार्टी 40 से कम सीटों पर सिमट गई।

सीएम यादव ने 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए 1836 करोड़ रुपए

भोपाल/माखनगर (नप्र)। नर्मदापुरम के माखन नगर (बाबई) से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल 2026 का पहला बड़ा तोहफा देते हुए 'लाड़ली बहना योजना' की 32वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार बहनों के खातों में 1250 रुपये के बजाय बढ़ी हुई राशि यानी 1500-1500 रुपये जमा किए गए हैं।

1.25 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ- मुख्यमंत्री ने एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,836 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। गौरतलब है कि सरकार ने नवंबर महीने से ही योजना की राशि में 250 रुपये का इजाफा कर इसे 1500 रुपये प्रति माह कर दिया था।

गैस सिलेंडर सब्सिडी का भी हुआ भुगतान- लाड़ली बहना योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना की सब्सिडी भी जारी की। प्रदेश की लगभग 29 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 90 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि ट्रांसफर की गई है। इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रसोई खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने माखन नगर (बाबई) के रोड शो में जनता का अभिवादन किया।

'समृद्धि यात्रा' चुनावी नहीं, विकास के मूल्यांकन की कसौटी

● बिहार में नीतिश कुमार के 5 साल तक टिके रहने के संकेत

पटना (एजेंसी)। 'समृद्धि यात्रा' पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने एक बार फिर अपने गठबंधन के साथी दल के साथ-साथ विपक्ष को भी चौंका दिया। इस कड़ाके के ठंड में सीएम नीतिश कुमार ने निकल कर एक साथ कई प्रश्नों के जवाब तो दे डाले, पर एक अनुत्तरित सा प्रश्न भी खड़ा कर गए। आम तौर पर राजनीतिक गलियारों में नीतिश कुमार के नेतृत्व में मिली बंपर जीत के साथ ही यह प्रश्न खड़ा होने लगा कि नीतिश कुमार के बाद कौन? यह सवाल महज सवाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर अस्थिरता का माहौल भी गहराने लगा। राजनीति के 'चाणक्य' कहे जाने वाले नीतिश कुमार ने एक ही चाल से उन सारे सवालों का जवाब दे डाला कि पांच साल तक चिंता करने की कोई बात नहीं। संगठन और सत्ता दोनों ही सम्भल लेंगे। नीतिश कुमार की इस यात्रा के बाद जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निशांत कुमार की आड़ में सत्ता के हस्तांतरण की बात नहीं करते। जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने अपने बयान में नीतिश कुमार और निशांत कुमार को लेकर पार्टी के भीतर द्वंद्व पर कहते हैं-निशांत कुमार बिहार की राजनीति में

प्रवेश करें, यह हम जैसे कार्यकर्ता भी चाहते हैं। मगर सत्ता में पीढ़ी का हस्तांतरण का समय अभी नहीं आया है। नीतिश कुमार पांच साल तक शासन करने में सक्षम है।

नीतिश कुमार ने रात्रि विश्राम को कहा ना!- मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने 'समृद्धि यात्रा' के दौरान रात्रि विश्राम नहीं करने का निर्णय लिया। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल यह यात्रा 'विकास यात्रा' के दौरान जिन परियोजनाओं की घोषणा की थी, इस यात्रा में उन योजनाओं के मूल्यांकन की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। प्लानिंग के स्तर पर या फिर जिला के स्तर पर स्थल चयन और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम तो विकास यात्रा के दौरान कर ही ली थी। सो, इस बार तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी हकीकत समझना है। लाभान्वित जनता से सीधे संवाद करना है। और यह काम दिन में तो किया ही जा सकता है। यह नीतिश कुमार हैं, जिन्होंने बेतिया जाने से पहले यहां के तमाम अधिकारियों से बात कर ली होगी और ये अधिकारी उनकी इच्छा के अनुसार फील्डिंग कर चुके होंगे। नीतिश कुमार उस प्लान के आधार पर कार्य करेंगे और वापस रात्रि विश्राम को पटना आ जाएंगे। रात्रि विश्राम के लिए पटना आने के पीछे एक बड़ा तर्क यह भी है कि यह यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं। चुनावी यात्रा में नीतिश कुमार उस जिले के अधिकारियों के जरिए या फिर संगठन के पदाधिकारियों के जरिए उस इलाके में कोई पुराना साथी हो, या फिर प्रखंड बार राजनीति का जानकार, उन सभी की सूची तैयार कर लेते थे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 17 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने की आ गई तारीख

● पार्टी ने जारी किया पूरा शेड्यूल, 20 जनवरी को होगी घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। पार्टी ने बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक पूरी होगी। बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया है। इससे पहले बिहार के पांच बार के विधायक को बीते 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब चुनाव के तारीखों के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है। पार्टी

ने राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी किए गए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक भाजपा चीफ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जा सकते हैं और उम्मीदवार उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दस्तावेजों की जांच 19 जनवरी को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी।

जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

● महाभियोग जांच समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही संसदीय समिति के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस

दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि अध्यक्ष ने समिति के गठन में कोई अवैधता नहीं की और यह माना कि जस्टिस वर्मा किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं और अदालत द्वारा किसी भी दखल की जरूरत नहीं है। 8 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हमें उन न्यायाधीशों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, साथ ही उन सदस्यों के अधिकारों के बीच भी संतुलन बनाना होगा जिन्हें कानून के तहत याचिका दायर करने और उसे स्वीकार कराने का स्वतंत्र अधिकार है। याचिका में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इंतजार किए बिना ही कमेटी का गठन कर दिया।

सांसद के करीबी की ड्रग फैक्ट्री पर छापा

रतलाम में 10 किलो एमडी, बंदूक, 91 कारतूस, दो मोर..चंदन की लकड़ियां मिलीं

रतलाम (नप्र)। रतलाम जिले के चिकलाना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात करीब ढाई बजे की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 10 किलो से अधिक तैयार एमडी ड्रग, करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का केमिकल, 12 बोर की बंदूक, 91 कारतूस, दो मोर और चंदन की लकड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने छापे के दौरान 16 लोगों को हिरासत में लिया। करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद शुक्रवार दोपहर 3 बजे घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। महिलाओं को भी गिरफ्तार कर सीधे कालूखेड़ा थाने ले जाया गया। इस दौरान गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीण आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग करते रहे। जब आरोपियों को पुलिस वाहन में बैठाया जा रहा था, तब ग्रामीणों ने जय जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस के अनुसार, जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी, वह दिलावर खान पठान का है। दिलावर चिकलाना गांव का निवासी है और आजाद समाज पार्टी से जुड़ा रहा है। वह यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का करीबी बताया जा रहा है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम

● पीएम मोदी बोले-10 साल पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 2 लाख

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, लेकिन आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर पीएम ने कहा कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे यंग इनोवेटर्स, जिन्होंने नए सपने देखने का साहस

दिखाया। मैं उन सभी की बहुत-बहुत सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 10 सालों में भारत नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।

● स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है- मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े-बड़े घरानों के बच्चे ही लाते थे। क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग और सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब बच्चे सिर्फ नौकरी के ही सपने देख पाते थे।

मुख्यमंत्री ने किया महाभारत समागम का शुभारंभ

भारत भवन में 24 जनवरी 2026 तक होंगे सांस्कृतिक, वैचारिक आयोजन

भोपाल। वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा महाभारत पर केन्द्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। शुभारंभ अवसर पर इण्डोनेशिया के प्रतिष्ठित नाट्य समूह द्वारा प्रस्तुत 'भीष्म' नाट्य प्रस्तुति तथा 'कर्मचक्र की गाथा' ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इमर्सिव डोम थियेटर, प्रदर्शनियाँ नेपथ्य, अस्त्र-शस्त्र, चक्रव्यूह एवं पताकाएँ, भारतीय कठपुतली, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की पत्रिका एवं वेबसाइट तथा वीर भारत न्यास के प्रकाशन- सभ्यताओं की सॉस (वैश्विक कविताओं का संकलन), भूली बिसरी सभ्यताएँ पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। समागम को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने कहा कि भारत भवन के इस परिसर में महाभारत जैसा भव्य समागम के आयोजन के लिए मैं संस्कृति विभाग और वीर भारत न्यास को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि महाभारत केवल युद्ध का आख्यान नहीं, बल्कि मानवता को विवेक, संवाद और शांति का मार्ग दिखाने वाला महाकाव्य है। आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रहा है, तब महाभारत का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से पहले संवाद और शक्ति से पहले करुणा का चयन ही सच्चा धर्म है। मध्यप्रदेश की धरती से इस समागम के माध्यम से हम विश्व को यह संदेश दे रहे हैं कि सभ्यताओं का भविष्य टकराव में नहीं, बल्कि सहअस्तित्व और औदार्य में सुरक्षित है।

एलओसी के पास फिर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन

● 5 दिन में तीसरी घटना, सेना की फायरिंग के बाद भागे

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों में गुरुवार शाम को रामगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी-अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक, यह ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आए। पुंछ में एलओसी पर पोस्ट के पास एक ड्रोन देखा गया। इसी तरह, रामगढ़

सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक और ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। पिछले पांच दिनों में ड्रोन दिखने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले, 13 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में दो बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। इसके बाद सेना ने फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर लौट गए थे। वहीं 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर, धरमसाल सेक्टर, रियासी, सांबा और पुंछ के मंकोट सेक्टर में एक साथ पांच ड्रोन स्पॉट किए गए थे।

रिस्क लेने वालों को अब रिस्पेक्ट मिलती है

पीएम बोले-10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 2 लाख से ज्यादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग पर और ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो

विजन है। ये अलग-अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का जरिया है। रिस्क-टेकिंग पर मैं जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने को तैयार नहीं होता, जिन कामों को दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुआ, क्योंकि उनमें चुनाव हारने और कुर्सी जाने का डर था। मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं।

आज रिस्क-टेकिंग, मैनस्ट्रीम बन चुका है

आज रिस्क-टेकिंग, मैनस्ट्रीम बन चुका है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वालों को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, उन्हें अब रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क-टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रींज मानते थे, वो अब फेशन बन रहे हैं। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर दो लाख से ज्यादा हो गई है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब सवा सौ सक्रिय यूनिकॉर्न हैं। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की सक्सेस स्टोरी की बात होगी, तब युवा खुद साबित करेंगे।

● यह कितने ही सपनों के साकार होने की यात्रा -ये कितने ही सपनों के साकार होने की यात्रा है। आज से 10 साल पहले, विज्ञान भवन में 500-700 नौजवानों के बीच इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए-नए लोग आ रहे थे, उनके अनुभव मैं सुन रहा था और मुझे याद है एक बेटी, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की तरफ जा रही थी। नौकरी छोड़कर वो कोलकाता अपनी मां से मिलने गई और मां से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है।

यूपीए सरकार के 2 और कानून में होगा बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानूनों- शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनी, तो संसद में नए कानून (बिल) भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार यह भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए। परामर्श प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो विकास से जुड़े अधिकार बनाए गए थे, उनमें 3 बड़ी कमियां थीं। उन कानूनों से न तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिल पाई और न ही हर परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है कि सभी लाभार्थियों का पूरा (100 फीसदी) रजिस्ट्रेशन हो। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर और सही तरीके से पहुंचना चाहिए।

डीआरजी दंपति समेत 40 मकानों पर चला बुलडोजर

● 35 और टूटेंगे, बीजापुर में रोते-रोते लोगों ने छोड़ा अपना घर ● बोले-प्रशासन घर तोड़ रहा, गांव जाएंगे तो नक्सली मार देंगे

बीजापुर (एजेंसी)। बीजापुर में न्यू बस स्टैंड के पीछे अब तक 40 अवैध मकान ढहाए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) दंपती का घर भी तोड़ा गया, जबकि जवान नाइट ड्यूटी पर था। घर में मौजूद उसकी पत्नी के मुताबिक, वे यहां 2006 से रह रहे हैं, और गांव में उनके पास कोई घर नहीं है। कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं की रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिलाएं सवाल कर रही थीं- हम कहां जाएंगे। पीड़ित गंगा माड़वी का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ पिछले 4 सालों से यहां रह रहे हैं। नक्सली हिंसा के कारण वे अपने गांव को छोड़कर यहां आए थे। प्रशासन से बातचीत के बाद उन्होंने घर बनाया और नियमित रूप से टैक्स भी जमा कर रहे थे। अब प्रशासन घरों को तोड़ रहा है। गांव वापस गए तो नक्सली मार देंगे। गंगा के मुताबिक तीन महीने पहले उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला था, जिस पर मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्हें यह भरोसा भी दिलाया गया था कि घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब अचानक गिराया जा रहा है।

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्व भारत के यात्रियों को राहत

भोपाल (नप्र)। लंबी दूरी की यात्राओं में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने अहम फैसला लिया है। भोपाल मंडल होकर संचालित चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों आरकेएमपी-अगरतला, जबलपुर-पुणे, जबलपुर-कोयंबटूर और जबलपुर-बांद्रा टर्मिनस-की संचालन अवधि मार्च 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2030 तक कर दी गई है। इससे मध्यप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्व भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को

सीधा फायदा मिलेगा। आरकेएमपी-अगरतला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (01665/01666) की अवधि बढ़ने से भोपाल, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को त्रिपुरा और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों तक सीधी रेल सुविधा लंबे समय तक मिलती रहेगी। यह ट्रेन खासतौर पर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भारी मांग में रहती है। इसी तरह जबलपुर-पुणे (02132/02131) और जबलपुर-बांद्रा टर्मिनस (02134/02133) स्पेशल ट्रेनों से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन (02198/02197) के संचालन विस्तार से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे के अनुसार ये सभी स्पेशल ट्रेनें होली, ग्रीष्मकालीन अवकाश, त्योहारी सीजन, सर्दियों और अतिरिक्त भीड़ वाले समय में संचालित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को कन्फर्म यात्रा का बेहतर विकल्प मिल सके।

वेनेजुएलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रम्प को दिया

मचाडो के प्रेसीडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रम्प का समर्थन नहीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद माचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलावासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।' बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने ट्रम्प को अपना पुरस्कार सौंपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं, व्हाइट हाउस ने भी यह नहीं बताया कि ट्रम्प ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मचाडो ने बाहर जुटे समर्थकों से स्पेनिश में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि, ट्रम्प ने अब तक माचाडो को वेनेजुएला की नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। इसकी बजाय वे वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ काम कर रहे हैं।

पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन उपाधि नहीं

ट्रम्प हमेशा नोबेल शांति पुरस्कार लेने की इच्छा जताते रहे हैं। जब यह मचाडो को मिला तो उन्होंने नाराजगी जताई। दूसरी ओर नोबेल कमेटी ने पहले कहा था कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। न ही इसे साझा किया जा सकता है और न ही किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह निर्णय अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य रहेगा। वहीं, गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक से पहले नोबेल संस्थान ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एक पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की उपाधि नहीं बदल सकती। अक्टूबर 2025 में मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 'वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके प्रयासों और तानाशाही से शांतिपूर्ण लड़ाई' के लिए यह सम्मान मिला था।

मचाडो बोली-

वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को मेडल लौटाया- मचाडो ने ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार देते हुए 1825 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के हीरो मार्क्विस डे लाफायेट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 200 साल पहले मार्क्विस डे लाफायेट ने जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल साइमन बोलिवर को दिया था, जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच स्वतंत्रता की लड़ाई में भाईचारे का प्रतीक था। अब, बोलिवर के लोगों ने वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी (ट्रम्प) को नोबेल मेडल लौटाया है।

लाफायेट ने दक्षिण अमेरिका के आजादी के नेता साइमन बोलिवर को एक खास सोने का पदक भेजा। इस पदक पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर बनी हुई थी। यह तोहफा दोनों देशों के बीच भाईचारे और तानाशाही के खिलाफ साझा लड़ाई का प्रतीक था। बोलिवर ने इस पदक को बहुत सम्मान दिया और इसे हमेशा पहनते रहे। वेनेजुएला के लोग खुद को बोलिवर के वंशज मानते हैं।

पेसा के सफल क्रियान्वयन और उपलब्धियों का हो व्यापक जनजागरण : राज्यपाल

लोक भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में पेसा, अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को

विकास के नए आयाम दिए हैं। जनजातीय समुदाय और ग्राम सभाओं में पेसा नियम की जन जागरूकता आवश्यक है। संबंधित विभाग पेसा नियम के सफल क्रियान्वयन और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। ग्राम सभा और समितियों की विशेष सफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने नवाचार करें। राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में पटेल भी मौजूद रहे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि पेसा नियमों के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समितियों द्वारा स्थानीय स्तर पर विवाद निवारण की सफलता अत्यंत उत्साहवर्धक है। यह सामाजिक सौहार्द्र एवं भाईचारे की भावना को मजबूत कर रही है। जनजातीय समुदाय को अनावश्यक मुकदमों एवं आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाने का सराहनीय कार्य कर रही है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। संबंधित विभाग इन सफलताओं की बुकलेट बनाएं और वितरित करें। बैठक में पेसा ग्राम सभाओं के वित्तीय पक्ष, वन ग्रामों को राजस्व में परिवर्तन, ग्राम सभाओं के नजरी नक्शा, लंबित प्रस्ताव, पट्टों की स्थिति, तेंदुपत्ता संग्रहण भुगतान आदि विभिन्न बिन्दुओं की विस्तार से समीक्षा की। राज्यपाल श्री पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने पेसा नियमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार, आगामी लक्ष्यों, उपलब्धियों, कठिनाईयों और उनके व्यावहारिक समाधान के विभागीय प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पेसा मोबेलाइजर्स के मानदेय के भुगतान संबंधी आगामी नवाचार प्रयासों को बताया।

मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा के वार्षिक सम्मेलन का कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के सभागार में दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया

नक्सलवाद कमरे में बिस्तर के नीचे घूमने वाले सांप की तरह थे जिनका फन हमारी पुलिस ने कुचला

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी में फैले नक्सलवाद की सांप से तुलना की। उन्होंने कहा कि एक कमरे में मखमल के गद्दे पर किसी को सोने के लिए कह दिया जाए और उस कमरे में सांप घूमते रहें तो यह कैसे हो सकता है कि कोई आसानी से सो सके। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि पुलिस ने इस समस्या को समझा और सांप का फन कुचलकर नक्सल मूवमेंट को खत्म कर दिया है।

सीएम डॉ. यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ये बात कही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर विधिवत रूप से आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि परिवार और व्यक्तिगत जिन्दगी को छोड़ पुलिस लोगों के लिए काम करती है। हमारे भारत की पुलिस अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है।

प्रदेश पुलिस देश के लिए आदर्श उदाहरण

नए कानून लागू करने में प्रदेश पुलिस देश के लिए आदर्श उदाहरण है। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों सहित सभी तरह के संगठित गिरोह और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। डॉ. यादव ने प्रदेश की धरती से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और जन सेवा की भावना को और मजबूत करते हुए मध्य प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा का आदर्श प्रदेश बनाए रखना हम सब का लक्ष्य हो।

सीएम यादव ने कहा कि आजादी के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ही आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। हमारे यहां आईएएस, आईपीएस अफसरों ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सारे विभाग महत्वपूर्ण हैं लेकिन पुलिस की चुनौतियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संगठित अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें मध्य प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा का आदर्श प्रदेश बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को जल्द ही प्रमोशन की स्वीकृति का समाचार मिलेगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग में पर्याप्त भर्तियां की जाएंगी।

डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी में कई तरह की चुनौतियां होती हैं। इसके बावजूद वे अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। सभी पुलिसकर्मी अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के लिए वर्ष 2025 उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रदेश सरकार और पुलिस नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रविरोधी ताकतों को मध्यप्रदेश पुलिस जड़ से खत्म कर रही है। राज्य में संगठित अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। पुलिस लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए हर कदम पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई देती है। नशा विरोधी अभियान में प्रदेश पुलिस निरंतर सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है।

डीजीपी ने किया स्वागत- आईपीएस सर्विस मीट में पहुंचे मुख्यमंत्री का पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और भारतीय पुलिस सेवा संघ के अध्यक्ष चंचल शेखर ने पुष्प गुच्छ और पौधा भेंट कर स्वागत किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने स्वागत उद्बोधन दिया।

समाधान योजना में अब 31 जनवरी 2026 तक मिलेगी सौ फीसदी तक सरचार्ज में छूट

समाधान योजना में अब तक 11 लाख 88 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में अब तक 11 लाख 88 हजार 240 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। अब तक 632 करोड़ 92 लाख रूपये मूल राशि जमा हुई है। साथ ही 276 करोड़ रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए समाधान योजना के प्रथम चरण की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक विस्तार किया गया है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3 लाख 84 हजार 130 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 403 करोड़ 69 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 215 करोड़ 95 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 3 लाख 98 हजार 470 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। मूल राशि 122 करोड़ 79 लाख रूपये जमा हुई है तथा 43 करोड़ रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रान्तर्गत 4 लाख 5 हजार 640 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। कुल मूल राशि 106 करोड़ 44 लाख रूपये जमा हुई है। साथ ही 16 करोड़ 77 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ हो रहा है जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कुछ कम हो जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से हुई जो कि 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा। इसके बाद द्वितीय और अंतिम चरण शुरू होगा जो कि 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।

आज गडकरी करेंगे 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 17 जनवरी का दिन मध्यप्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। इस दिन केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ रूपये से अधिक लागत से निर्मित एवं प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 181 किलोमीटर लम्बी ये परियोजनाएँ मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगी और प्रदेश के सड़क एवं परिवहन अवसंरचना विकास की दिशा में एक ओर ऐतिहासिक अध्याय जुड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को मिल रही ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, आवागमन की सुगमता और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और कुशल, प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। ये केंद्र सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इंदौर के बाद खरगोन में दूषित जल पीने से 14 लोग बीमार

लीकेज के बाद घरों में पहुंचा गंदा पानी

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गंदे पानी ने कहर बरपाया है। मंडलेश्वर नगर के एक वार्ड में दूषित पानी का पता चला है। पानी पीने से 14 लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद लोगों का इलाज किया गया है। समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो इंदौर जैसी घटना घट सकती थी।

14 लोग हुए बीमार

दरअसल, खरगोन जिले के मंडलेश्वर नगर के एक वार्ड के कुछ हिस्सों में पेयजल पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी सप्लाई होने से 14 लोग बीमार हो गए। बीमारों में महिला और पुरुष शामिल हैं। सभी मरीजों का इलाज मंडलेश्वर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने घर घर पहुंच कर किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

पेट दर्द और दस्त की शिकायत

मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी (बीएमओ) डॉ. सोनू मंडलोई ने बताया कि पिछले तीन दिनों में वार्ड नंबर 8 की एक गली में कुल 14 मरीज चिन्हित हुए । मरीजों को मुंह में छाले, पेट दर्द, दस्त और ऐंठन जैसी शिकायतें थीं। सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दवाइयां दी गईं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित गली में लगातार सर्वे किया गया है और फिलहाल कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अधिकारियों ने किया निरीक्षण

डॉ. मंडलोई ने बताया कि मरीजों ने नलों से गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायत की थी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना नगर परिषद को दी, जिसके बाद पेयजल व्यवस्था की जांच की गई। वहीं, नगर परिषद मंडलेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) संजय रावल ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज की जानकारी मिलते ही तत्काल सुधार कार्य कराया गया। मरम्मत के बाद क्षेत्र में साफ पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एसडीएम मंडलेश्वर के साथ मौके का निरीक्षण भी किया गया। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति की निजी पाइपलाइन लीक हो रही थी, जहां जमा गंदा पानी नाली के पानी के साथ मिलकर पेयजल लाइन को प्रदूषित कर रहा था। फिलहाल समस्या का पूर्ण समाधान कर लिया गया है और क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी गंदे पानी की शिकायत हो तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की दी शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था। हमारे देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनकर सफलता के नित नए अध्याय लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्टार्टअप के लिए समर्पित सभी युवाओं को मंगलकामनाएं दीं हैं।

पीएम सूर्य घर योजना में अब तक 29 हजार 174 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 227 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

योजना में 3 किलोवॉट के सौर संयंत्र लगाने पर 78 हजार की मिलेगी सब्सिडी

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना में अब तक कुल 29 हजार 174 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इनके खातों में 227 करोड़ 39 लाख रूपये से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में एक किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रूपये, 2 किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा 3 किलोवॉट या उससे अधिक के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए पीएम सूर्य घर योजना

की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट अथवा उपाय ऐप, वॉट्सऐप चेटबॉट व टोल फ्री नं 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रूपये तक की कमी परिलक्षित हो रही है। कंपनी ने कहा कि जिन रूफटॉप सोलर प्लांट में नेट मीटर के साथ मोडेम व सिम लगे होने के बाद भी अगर डाटा कम्युनिकेशन का अभाव है, तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किए गए हैं। कम्युनिकेशन फिर भी स्थापित नहीं होने की अवस्था में वेंडर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूली बच्चों को बेरहमी से पीटता था ड्रग तस्कर

एक साल पहले हुई थी अबान की शिकायत, जांच समिति बनी, कार्रवाई नहीं हुई

भोपाल (नप्र)। इंदौर में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सेंट माइकल स्कूल का संचालक अबान शकील का एक और कारनामा सामने आया है। आरोपी स्कूल में बच्चों को बेरहमी से पीटता था। पिछले साल जनवरी महीने में उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र को इतना पीटा कि उसके दोनों पैरों की चमड़ी निकल गई थी। छात्र का कहना है कि टीचर ने उसके पैरों पर फुटबॉल के शूट की तरह मारा। लगातार लात मारी।

छात्र के परिजन ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत की थी। जिसकी पर जांच समिति बनाई गई थी। हालांकि समय बीतने के साथ ही जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

फुटबॉल शूट की तरह पीटा था- घटना के बाद बच्चे ने बताया था कि अबान सर ने शूज से मारा। जब मैं वहां खड़ा था, तब वह मुझे फुटबॉल के शूट की तरह मार रहे थे। मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझे मारा। पहले भी मेरी पिटाई हुई थी। अन्य बच्चों को भी अबान सर इसी तरह पीटते थे।

11वीं कक्षा के छात्र को पीटने की घटना 9 जनवरी 2025 की सुबह 8:30 बजे की थी। स्कूल परिसर में एक अन्य छात्र के साथ बच्चे विवाद हो गया था। तब अबान ने छात्र को बेरहमी से पीटा था। वहीं सूत्रों की माने तो बाद में अबान और शिकायतकर्ता छात्र के परिजनों के बीच राजीनामा हो गया था। हालांकि घटना के बाद छात्र की चोटों के साथ वीडियो सामने आए थे।

पुलिस को थार में 5.5 ग्राम एमडी मिली

13 जनवरी को इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि अबान शकील कनाडिया में नशीले पदार्थों की खेप लेकर आने वाला है। मुखबिर के बताए रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने अबान की थार को रोक लिया। तलाशी में 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई।

शुरुआती पूछताछ में अबान ने बताया कि किसी को शक न हो, इसलिए ड्रग सप्लाई के लिए वह खुद की ही थार का उपयोग करता था।

ड्रग्स पैडलर बाबा ने दी थी एमडी

अबान शकील ने इंदौर पुलिस को बताया कि उसे ड्रग्स बाबा ने दी थी। भोपाल का ड्रग पैडलर बाबा पार्टी और पब में नशा करने वालों को ड्रग्स मुहैया कराता है। अबान ने बताया कि वह शनिवार को दोस्तों के साथ पार्टी करता था। इसी दौरान एक पब में उसकी बाबा से पहचान हुई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बनाई थी जांच समिति

इस घटना की शिकायत छात्र के परिवार ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार से की थी। साथ ही छात्र को आई चोट का वीडियो भी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत जांच समिति का गठन किए जाने के दावे किए थे।

संपादकीय

मुंबई में 'बीएमसी' चुनाव का नया इशारा

मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ठाकरे ब्रदर्स का बरसों से चला आ रहा वर्चस्व ख़त्म हो गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के लंबे वर्चस्व को चुनौती देते हुए, महायुति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पहली बार बीजेपी को मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में बहुमत मिला, जो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना खेमे का साथ बीजेपी को रास आया, जिसने ठाकरे परिवार के पारंपरिक गढ़ को ढहा दिया। यह नतीजा न केवल स्थानीय शासन की दिशा बदलेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। मुंबई महानगरपालिका, दुनिया की सबसे अमीर नगर निगमों में शुमार, ठाकरे परिवार का किला रही है। 1968 से शिवसेना ने यहां लगातार वर्चस्व बनाए रखा। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में बीएमसी पर उनका कंट्रोल रहा। लेकिन, 2022 के विद्रोह के बाद शिंदे गुट ने चुनौती दी। अब 2026 के चुनावों में बीजेपी को 128 सीटें (कुल 227 में से) मिलीं, जबकि शिवसेना (शिंदे) को 75 और एमएनएस को 20। शिवसेना (यूबीटी) को मात्र 30 सीटें ही नसीब हुईं। यह पहली बार है जब बीजेपी को स्वतंत्र बहुमत मिला, जो 227 का आधे से ज्यादा है। राज ठाकरे की एमएनएस भी अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुई। यह जीत महायुति की एकजुटता का प्रमाण है। शिंदे का साथ बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। मुंबई जैसे शहर में जहां विकास, बुनियादी ढांचा और आवास मुद्दे प्रमुख हैं, बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ-साथ शहरी विकास के एजेंडे पर जोर दिया। ठाकरे ब्रदर्स की विभाजित सेनाएं एक-दूसरे के खिलाफ लड़ी, जिससे उनका वोट बैंक बंट गया। उद्धव का 'मराठी मानूस' का नारा भी अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। यह नतीजा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए बूस्टर है। 2024 के लोकसभा चुनावों में महायुति की मजबूती देखी गई थी, अब बीएमसी की जीत ने इसे और मजबूत किया। राज्य सरकार की स्थिरता भी बढ़ेगी, क्योंकि बीएमसी का बजट 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इससे सड़कें, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। बीजेपी नेता जैसे अमित शाह ने इसे 'मोदी की लोकप्रियता' का प्रमाण बताया। दूसरी ओर, ठाकरे ब्रदर्स के लिए यह झटका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में नाम विवाद हारना पड़ा और अब बीएमसी हार ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राज ठाकरे, जो कभी बाला साहेब के उत्तराधिकारी बने, अब हाशिए पर हैं। एमएनएस का वोट शेयर घटकर 8 प्रतिशत रह गया। मुंबई की 1.2 करोड़ आबादी के लिए यह बदलाव मायने रखता है। बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ठाकरे युग में बड़े ठेके और अनियमितताएं चर्चा में रहीं। अब बीजेपी का बहुमत पारदर्शिता ला सकता है। उदाहरण के लिए एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव तेज होगी और मुंबई को 'वर्ल्ड क्लास सिटी' बनाने की योजनाएं लागू होंगी। हालांकि, विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि बीजेपी का 'उत्तर भारतीय' एजेंडा मराठी अस्मिता को नुकसान पहुंचा सकता है। शहरी गरीबों, झोपड़पट्टी वासियों के लिए आवास योजनाएं महत्वपूर्ण होंगी। पर्यावरणीय मुद्दे जैसे तटीय सड़क परियोजना पर तेजी आएगी। लेकिन ट्रैफिक, बाढ़ और महंगाई के रूप में चुनौतियां बरकरार हैं। ठाकरे ब्रदर्स का मुंबई में खेल खत्म होते दिख जरूर रहा है, लेकिन राजनीति अप्रत्याशित है। उद्धव शायद विपक्षी एकता से पुनरुत्थान की कोशिश करेंगे। जबकि, इस जीत से शिंदे-फडणवीस गठजोड़ मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह बीजेपी की शहरी रणनीति का हिस्सा है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है और यह जीत विकास और शासन पर आधारित लगती है। मुंबई अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। क्या यह स्थायी परिवर्तन होगा या अस्थायी यह तो समय बताएगा।

पश्चिम एशिया की राजनीति पर ईरान का संकट

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

आज का ईरान इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक बदहाली, सामाजिक अशांति और भू-राजनीतिक टकराव एक-दूसरे में घुलकर एक गहरे और अस्थिर संकट का रूप ले चुके हैं। ईरान के विभिन्न शहरों में भड़क रहे जन-आंदोलन केवल क्षणिक जनाक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे उस संरचनात्मक विफलता की ओर संकेत करते हैं, जिसकी जड़ें बेलगाम महँगाई, बढ़ती बेरोज़गारी, मुद्रा के अवमूल्यन और शासक व्यवस्था तथा युवा, हताश होती जा रही आबादी के बीच गहराते अंतर में निहित हैं। वर्तमान असंतोष को पूर्व आंदोलनों से अलग करने वाली बात इसकी व्यापकता और निरंतरता है। यह असंतोष वर्ग, जातीयता और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करता हुआ आर्थिक पीड़ाओं को राजनीतिक असहमति में रूपांतरित कर चुका है। तेहरान जब इस आंतरिक उथल-पुथल को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, तब इसके प्रभाव ईरान की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किए जा रहे हैं, जिससे पश्चिम एशिया में भूचाल-सरीखे झटके उत्पन्न हो रहे हैं और भारत सहित क्षेत्रीय व वैश्विक शक्तियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने को विवश होना पड़ रहा है।

ईरान के घरेलू संकट के मूल में एक अत्यंत दबावग्रस्त अर्थव्यवस्था है। वर्षों से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने, जिनके साथ शासन की अक्षमता और क्षेत्रीय हस्तक्षेप भी जुड़े रहे, आम नागरिक के जीवन की बुनियादी संरचना को कमजोर कर दिया है। महँगाई ऐसे स्तर तक पहुँच चुकी है जिसने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है और रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं को आम लोगों की पहुँच से बाहर कर दिया है। रियाल मुद्रा का तीव्र अवमूल्यन केवल क्रय-शक्ति की गिरावट का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक प्रबंधन क्षमता पर जनता के विश्वास के क्षरण का भी संकेत है। जहाँ पहले विरोध प्रदर्शन मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग या किसी एक सामाजिक समूह तक सीमित रहते थे, वहीं वर्तमान आंदोलन में बाज़ारों के व्यापारी, श्रमिक, छात्र और हाशिए पर खड़े समुदाय सभी शामिल हैं। यह साझा आर्थिक पीड़ा एक ऐसे असामान्य गठबंधन को जन्म दे रही है, जो व्यवस्था के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रहा है।

समय के साथ यह आर्थिक संकट राजनीतिक रूप धारण करता जा रहा है। अब प्रदर्शनकारी केवल नीतिगत विफलताओं पर प्रश्न नहीं उठा रहे, बल्कि शासन-व्यवस्था की वैधता पर भी सीधा सवाल कर रहे हैं। राज्य की प्रतिक्रिया, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, इंटरनेट बंदी और बल प्रयोग शामिल हैं- नई नहीं है, किंतु इस बार दाँव कहीं अधिक ऊँचे हैं। ईरान की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है, वैश्विक दुनिया से अधिक जुड़ी हुई है और उन वैचारिक आख्यानों को स्वीकार करने को तैयार नहीं, जो हर असहमति को विदेशी साज़िश बताकर खारिज कर देते हैं। दमन की प्रत्येक कार्रवाई शासकों और जनता के बीच की खाई को और चौड़ा कर रही है, जिससे शासन की स्थिरता और अधिक असुरक्षित होती जा रही है तथा लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता का खतरा बढ़ रहा है।

इसके बावजूद, ईरानी शासन के पास नियंत्रण के शक्तिशाली साधन अब भी मौजूद हैं। इस व्यवस्था के केंद्र में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) है, जो केवल एक सैन्य बल नहीं, बल्कि एक विशाल राजनीतिक-आर्थिक संरचना भी है, जिसकी व्यवस्था की निरंतरता में गहरी हिस्सेदारी है। सुरक्षा, उद्योग और क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्कों में आईआरजीसी का प्रभाव शासन को असंतोष दबाने और

सीमाओं के बाहर शक्ति प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है। किंतु राजनीति का यह बढ़ता सैन्यीकरण दीर्घकालिक लागत भी लेकर आता है। जब सहमति का स्थान बल ले लेता है, तब व्यवस्था की आंतरिक दुर्बलता उजागर हो जाती है और सुधार या संवाद की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

ईरान का यह आंतरिक संकट पहले से ही संघर्षों से जूझ रहे क्षेत्र में गूंज पैदा कर रहा है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में सहयोगी मिलिशिया और राजनीतिक ताकतों के माध्यम से ईरान का प्रभाव फैला हुआ है, जिसे प्रायः 'प्रतिरोध की धुरी' कहा जाता है। घरेलू अस्थिरता के लंबे खिंचने से यह प्रश्न उठता है कि क्या ईरान इस नेटवर्क को बनाए रखने में सक्षम रहेगा। एक कमजोर ईरान जहाँ अपने बाहरी हस्तक्षेप कम कर सकता है, वहीं वह राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने या कथित खतरों को रोकने के लिए अधिक आक्रामक रुख भी अपना सकता है। यह अनिश्चितता विशेष रूप से खाड़ी देशों को चिंतित करती है, जिन्हें ईरान के पतन और उसके आक्रामक व्यवहार दोनों से भय है।

ईरान की उथल-पुथल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया एक परिचित विभाजन को दर्शाती है। अमेरिका और इज़राइल इस संकट को मुख्यतः सुरक्षा और परमाणु जोखिम के दृष्टिकोण से देखते हैं। वॉशिंगटन के लिए ईरान पर आंतरिक दबाव उसके क्षेत्रीय व्यवहार और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने का एक साधन है, भले ही इससे गलत आकलन का खतरा बना रहे। इज़राइल ईरान को अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है और अस्थिरता को एक अवसर तथा एक जोखिम, दोनों के रूप में परखता है। अवसर इसलिए कि शत्रुतापूर्ण शासन कमजोर हो सकता है, और जोखिम इसलिए कि अराजकता परमाणु तनाव या प्रॉक्सी युद्धों को तेज कर सकती है। इस संदर्भ में सार्वजनिक बयानबाज़ी और गुप्त कार्रवाइयाँ तनाव घटाने के बजाय ईरान की कठोरता को और बढ़ा सकती हैं।

इसके विपरीत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी अधिक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता में भारी निवेश कर चुके ये देश जानते हैं कि ईरान का पतन शरणार्थी संकट, ऊर्जा बाज़ारों में उथल-पुथल और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे सकता है। वे ईरानी प्रभाव में कमी का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शक्ति-शून्य से भी डरते हैं जो उनकी विकास योजनाओं को पटरी से उतार दे। यह व्यावहारिक तटस्थता क्षेत्र में वैचारिक टकराव से हटकर जोखिम प्रबंधन और आर्थिक प्राथमिकताओं की ओर बढ़ते झुकाव को दर्शाती है।

रूस और चीन ईरान की स्थिति को आंतरिक मामला बताते हुए संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप पर बल देते हैं। मॉस्को के लिए ईरान सीरिया में एक रणनीतिक साझेदार और पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध संतुलन का साधन है, जबकि बीजिंग ऊर्जा सुरक्षा और बेल्ट एंड रोड पहल के तहत दीर्घकालिक संपर्क को प्राथमिकता देता है। फिर भी, ये दोनों शक्तियाँ ईरान की आंतरिक दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित करने में सक्षम या इच्छुक प्रतीत नहीं होतीं। उनका समर्थन कूटनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, किंतु वह घरेलू वैधता या आर्थिक पुनरुत्थान का विकल्प नहीं बन सकता।

भारत के लिए ईरान की उथल-पुथल तात्कालिक और बहु-स्तरीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। प्रतिबंधों के कारण भले ही भारत का प्रत्यक्ष आर्थिक जुड़ाव कम हुआ हो, पर व्यापक प्रभाव अत्यंत गहरे हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत की पहुँच में ईरान की भू-रणनीतिक भूमिका अहम है, विशेषकर चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से। लंबे समय तक बनी रहने वाली अस्थिरता या कड़े प्रतिबंध इन संपर्क परियोजनाओं को कमजोर कर सकते हैं, जिससे भारत की रणनीतिक क्षमता और क्षेत्रीय आकांक्षाएँ प्रभावित होंगी।

ऊर्जा सुरक्षा भी भारत के लिए चिंता का एक बड़ा क्षेत्र है। प्रत्यक्ष संघर्ष के बिना भी ईरान में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता पैदा करती है, विशेषकर यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है। समुद्री व्यापार मार्गों में बाधा आने से परिवहन और बीमा लागत बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव भारत में महँगाई पर पड़ेगा। यदि सैन्य टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका आर्थिक दुष्प्रभाव केवल तेल कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, निवेश और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा तक फैलेगा।

कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के सामने संतुलन साधने की कठिन चुनौती है। नई दिल्ली ने परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया में सावधान तटस्थता की नीति अपनाई है, जिसमें ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों–सभी से संबंध बनाए गए हैं। किंतु जैसे-जैसे महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा तीव्र होती जा रही है और क्षेत्रीय विभाजन गहरे हो रहे हैं, यह संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। भारत को वैचारिक पक्षधरता के बजाय स्थिरता और व्यावहारिक हितों को प्राथमिकता देते हुए रणनीतिक साझेदारियों और संवाद के बीच संतुलन साधना होगा।

आगे की राह पर दृष्टि डालें तो ईरान का संकट कई दिशाओं में विकसित हो सकता है। एक संभावना यह है कि एक अधिक सैन्यीकृत शासन उभरे, जहाँ आईआरजीसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धार्मिक नेतृत्व को पीछे धकेलते हुए सीमित प्रतिबंध राहत की कोशिश करे। दूसरी स्थिति अराजक विखंडन की हो सकती है, जहाँ लंबा असंतोष केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर कर दे और स्थानीय संघर्षों को जन्म दे। सबसे कम संभावित, किंतु सबसे परिवर्तनकारी विकल्प एक ऐसा वार्तामूलक संक्रमण होगा, जो आंतरिक सहमति और बाहरी मध्यस्थता के माध्यम से ईरान की राजनीतिक संरचना और क्षेत्रीय भूमिका को नया रूप दे। इन सभी रास्तों के पश्चिम एशिया और वैश्विक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होंगे।

तेहरान की उथल-पुथल केवल ईरान की समस्या नहीं है, बल्कि यह उस पूरे क्षेत्र की सहनशक्ति की परीक्षा है, जो पहले से ही संघर्ष, असमानता और बदलते शक्ति-संतुलनों से जूझ रहा है। ईरान इस संकट से कैसे निकलता है, यह पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक भविष्य को आकार देगा, चाहे वह ऊर्जा प्रवाह हो, सुरक्षा ढाँचा हो या महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा। भारत जैसे देशों के लिए चुनौती प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय रणनीति अपनाने की है, संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, अपने हितों की रक्षा करने और जहाँ संभव हो, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने की। तेहरान की घड़ी जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसके कंपन दूर-दराज़ तक महसूस किए जा रहे हैं, यह याद दिलाते हुए कि निर्णायक राज्यों के आंतरिक संकट कभी भी केवल उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहते।

डिजिटल शोर में शब्दों का शाश्वत स्वर

विश्व पुस्तक मेला पर विशेष

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक आयोजित हो रहा 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया तेजी से डिजिटल स्क्रीन पर सिमटती जा रही है और पढ़ने की आदत को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है। ऐसे में यह आयोजन न केवल किताबों का बाजार है बल्कि यह उम्मीद का वह दीप भी है, जो बताता है कि शब्दों की रोशनी अब भी मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित यह नौ दिवसीय मेला इस वर्ष कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार इसकी एंट्री पूरी तरह मुफ्त रखी गई है, जिससे ज्ञान तक पहुंच को सचमुच लोकतांत्रिक बनाया गया है। यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उस सोच का विस्तार है, जिसमें किताबों को किसी विशेष वर्ग की वस्तु नहीं बल्कि समाज की साझा धरोहर माना गया है। जब किसी मेले में प्रवेश के लिए जेब नहीं, केवल जिज्ञासा की जरूरत हो तो वहां ज्ञान अपने आप ही जनांदोलन का रूप ले लेता है।

इस वर्ष पुस्तक मेले की थीम 'भारतीय सैन्य इतिहासः शौर्य और ज्ञान @75' अपने आप में गहरी अर्थवत्ता समेटे हुए है। आजादी के 75 वर्षों की यात्रा में भारत ने केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय मूल्यों के साथ सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। हॉल नंबर 5 में बना थीम पवेलियन एक जीवंत इतिहास बनकर सामने आता है, जहां अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहती हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित श्रद्धांजलि स्थल यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों का परिणाम हैं। यहां प्रदर्शित 500 से अधिक पुस्तकें और 100 से अधिक थीम आधारित कार्यक्रम सैन्य इतिहास को केवल युद्धों की कथा नहीं, नीति, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं।

मेले का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तकों को पीढ़ियों को जोड़ने वाला सेतु बताया। पुस्तकें सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। डिजिटल युग में ज्ञान को सुलभ और समावेशी बनाने की सरकार की प्राथमिकता इस मेले में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के माध्यम से 23 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध 6000 से ज्यादा मुफ्त ई-बुक्स और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएं यह साबित करती हैं कि तकनीक और पुस्तकें एक-दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकती हैं। यह मेला इस बहस को भी विराम देता है कि डिजिटल माध्यम छपी हुई किताबों का स्थान ले लेंगे। यहां दोनों एक साथ, एक-दूसरे को मजबूत करते दिखाई देते हैं।

विश्व पुस्तक मेले की सबसे सुंदर तस्वीर शायद वह है, जहां जेन-जी के युवा, जिन्हें अक्सर 'स्क्रीन की पीढ़ी' कहकर किताबों से

दूर मान लिया जाता है, कागज के पन्नों में डूबे नजर आते हैं। पिक्सल्स के शोर से निकलकर वे शब्दों की गहराई को टटोलते हैं, अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढ़ते हैं और बताते हैं कि तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, सुकून आज भी किताबों में बंद ज्ञान से ही मिलता है। कतर पवेलियन में हिंदी और उर्दू के तैरते अक्षरों को देखकर तकनीक में निपुण युवा भी ठहर जाते हैं। वे लुप्त होते पारंपरिक खेलों, गायब होते पक्षियों और सांस्कृतिक स्मृतियों की किताबों में खुद को खोजते हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि युवा पीढ़ी को किताबों से दूरी नहीं बल्कि सही मंच और माहौल की जरूरत है।

इस वर्ष मेले की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक, 1000 से अधिक लेखक और वक्ता तथा 600 से ज्यादा साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे सचमुच वैश्विक उत्सव बनाते हैं। कतर का गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन का फोकस कंट्री होना भारत के सांस्कृतिक कूटनीति के विस्तार को दर्शाता है। स्पेन-भारत ड्यूल ईयर 2026 के तहत दोनों देशों के लेखकों और साहित्य को मिला मंच यह बताता है कि किताबें केवल पढ़ने की वस्तु नहीं बल्कि देशों के बीच संवाद का माध्यम भी हैं। पुस्तक मेले की सांस्कृतिक आभा इसे और जीवंत बनाती है। एम्फीथिएटर में हर शाम संगीत, कविता पाठ और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित हो रही हैं, जहां शब्दों के साथ सुर और अभिनय मिलकर संस्कृति का उत्सव रचते हैं। यहां बुजुर्ग किताबों के बीच बने सेल्फी प्वाइंट पर मुस्कुराहटें कैद करते हैं तो बच्चे 'किड्ज एक्सप्रेस' पवेलियन में कहानी सत्रों और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए सीखने की नई दुनिया में कदम रखते हैं। बच्चों के लिए यह मेला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो उनके मन में किताबों के प्रति आजीवन प्रेम बो सकता है।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का इतिहास भी इसकी महत्ता को और गहराई देता है। 1972 में विंडसर प्लेस से शुरू हुआ यह सफर आज 53 वर्षों का हो चुका है। तब केवल 200 प्रकाशक और कुछ ही देश शामिल होते थे, आज यह एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े बी2सी बुक फेयर में गिना जाता है। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि बदलते समय के बावजूद पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि हर दौर में नए रूप में सामने आया है। पुस्तकें केवल जानकारी नहीं देती, वे सोचने की क्षमता विकसित करती हैं। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया हमें त्वरित सूचनाएं तो देते हैं लेकिन अक्सर निष्क्रिय स्वीकृति की आदत डाल देते हैं। इसके विपरीत, पुस्तकें ध्यान, एकाग्रता और कल्पनाशीलता की मांग करती हैं। वे प्रश्न पूछने की क्षमता जगाती हैं और उत्तर खोजने का धैर्य सिखाती हैं। जब हम अकेले होते हैं, उदास या परेशान होते हैं, तब किताबें ही सच्ची मित्र बनकर हमारा साथ देती हैं। यही कारण है कि साहित्यकारों ने सदैव पुस्तकों को अखंड संपत्ति और नैतिकता की संदेशवाहक माना है।

आज जब समयाभाव के नाम पर हम पढ़ने से कतराने लगे हैं, तब विश्व पुस्तक मेला जैसे आयोजन हमें यह याद दिलाते हैं कि ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। किताबें विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और पहचानों को एक साझा विरासत के इर्द-गिर्द जोड़ती हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के शब्दों में, एक अच्छी किताब से ईमानदार मित्र कोई नहीं होता। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 इसी मित्रता का उत्सव है, जहां शब्द, विचार और संस्कृति एक-दूसरे से गले मिलते हैं। कुल मिलाकर, यह मेला केवल किताबों की खरीद-फरोख्त का स्थान नहीं बल्कि पढ़ने की संस्कृति का सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव है। यह युवाओं को यह संदेश देता है कि भविष्य केवल तकनीक से नहीं, विचारों से बनता है। यह बच्चों को यह अहसास कराता है कि किताबें उनके जीवन की साथी हो सकती हैं, साथ ही यह समाज को भी स्मरण कराता है कि शब्दों की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। बिना टिकट, बिना बाधा और बिना भेदभाव, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 ज्ञान, इतिहास, संगीत और संस्कृति का वह संगम है, जो सचमुच इसे बेहद खास बनाता है।

आर्थिक युद्ध और वैश्विक शांति का प्रश्न

अमेरिका-वेनेजुएला टकराव

डॉ. नंदिनी बासिष्ठा और
डॉ. सोविक मुखर्जी

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी टकराव यह दिखाता है कि इक्कीसवीं सदी में युद्ध अब केवल गोलियों और सेनाओं से नहीं लड़े जाते। बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के, आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव और राजनीतिक दबाव एक देश को अंदर से खोखला कर सकते हैं। वेनेजुएला इसका जीवंत उदाहरण है। अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेल निर्यात पर रोक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों से कटाव और व्यापारिक प्रतिबंधों ने आम नागरिकों के जीवन को सबसे अधिक कठिन बना दिया। महँगाई, दवाओं और खाद्य पदार्थों की कमी तथा बड़े पैमाने पर पलायन इस 'आर्थिक युद्ध' के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब प्रतिबंधों का घोषित उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव बनाना है, तो उनकी मार आम जनता पर क्यों पड़ती है? क्या यह सामूहिक दंड का ही एक नया रूप नहीं है?

संयुक्त राष्ट्र, जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा का संरक्षक माना जाता है, वेनेजुएला संकट में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहा है। सुरक्षा परिषद में राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रस्तावों पर वीटो की आशंका और महाशक्तियों के टकराव ने निर्णय प्रक्रिया को पंगु बना दिया। महासचिव एंतोनियो गुतारेस द्वारा 2021 में प्रस्तुत 'आवर कॉमन एजेंडा' में जिस वैश्विक शासन संकट की बात की गई थी, वेनेजुएला उसका स्पष्ट उदाहरण है। महासभा और मानवाधिकार परिषद की चर्चाएं और रिपोर्टें प्रभावशाली तो हैं लेकिन उनके पास प्रस्तावों को लागू कराने की शक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मानवीय सहायता तक सीमित रह गई है। जबकि मूल राजनीतिक संकट जस का तस बना रहा।

वेनेजुएला का मामला केवल एक देश तक सीमित नहीं है। यह समकालीन वैश्विक व्यवस्था की गहरी खामियों को उजागर करता है–अंतरराष्ट्रीय नियमों का चयनात्मक प्रयोग, कमजोर देशों की सीमित आवाज़ और बहुपक्षीय संस्थाओं में घटता विश्वास। जब शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय लेते हैं, तो वैश्विक शासन की विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है।

इस टकराव की सबसे प्रमुख विशेषता आर्थिक प्रतिबंधों का व्यापक उपयोग है। आज की वैश्विक राजनीति में प्रतिबंध सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प बन चुके हैं, विशेषकर तब जब प्रत्यक्ष युद्ध राजनीतिक रूप से महँगा हो। हालाँकि प्रतिबंधों का उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव बनाना बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में इनका सबसे गहरा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। वेनेजुएला में महँगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी, सार्वजनिक सेवाओं का पतन और बड़े पैमाने पर पलायन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। घरेलू नीतिगत विफलताओं के साथ-साथ प्रतिबंधों ने इस संकट को और गहरा किया है।

अमेरिका-वेनेजुएला टकराव दिखाता है कि आर्थिक युद्ध भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है जितना सैन्य संघर्ष। यदि बहुपक्षीय संस्थाओं को सशक्त नहीं किया गया और संवाद को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो ऐसे 'मौन संघर्ष' वैश्विक स्थिरता को लगातार कमजोर करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 'सस्टेनिंग पीस' एजेंडा हमें याद दिलाते हैं कि शांति दबाव से नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और समावेशी विकास से निर्मित होती है। बिना इस दृष्टिकोण के, वेनेजुएला जैसे संकट भविष्य में और गहराते रहेंगे।

आज शांति की परिभाषा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक समावेशन और संस्थागत न्याय भी उसका हिस्सा हैं। आर्थिक प्रतिबंध यदि मानवीय संकट को जन्म देते हैं, तो उन्हें शांति का साधन नहीं कहा जा सकता।

आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आर्थिक प्रतिबंधों पर स्पष्ट मानवीय निगरानी व्यवस्था विकसित करे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर गंभीर विमर्श हो और क्षेत्रीय कूटनीति व संवाद के वैकल्पिक मंचों को मजबूत किया जाए। वेनेजुएला हमें चेतावनी देता है कि यदि वैश्विक समस्याओं का समाधान दबाव और दंड से खोजा गया, तो अस्थिरता और बढ़ेगी। टिकाऊ शांति संवाद, सहयोग और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था से ही संभव है–न कि आर्थिक युद्ध के ज़रिये।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

हर किसी को आपकी खुशफहमी बर्दाश्त नहीं होती

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे
लेखक व्यंग्यकार हैं।

सुनो, एक मस्त चुटकुला पढ़ा है अभी। मैंने श्रीमती से कहा।

सुनाओ। वे बोली।

मैंने चुटकुला सुनाया और ठठाकर हँसा, यह सोचकर कि वे न हँसे पर मुस्कुरा तो देंगी ही, उनकी तरफ देखा, पर हुआ उल्टा, वे बोली- कितना पुराना है। आप अब पढ़ रहे हो?

सच कहता हूँ, मेरे सारे जोश और आनंद पर मानों घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। एक बार ऐसा ही कुछ करने का प्रयास मैंने किसी और के साथ किया, तब यही श्रीमतीजी, झट से बोल गई, तुम्हें भी न किसी से बात करने का कोई शऊर ही नहीं है।

'पर वह बात तो मैंने पहले भी सुनी थी। इसीलिए कहा दिया था।'

'पर ये शिष्टाचार नहीं है।'

'तो जो तुम करती हो मेरे साथ, वह क्या है?'

'तुम मेरे हो।'

'तो... अपनों के साथ शिष्टाचार नहीं होता? मन आया में कुछ भी कह दोगी।'

'अब यह जगह और समय नहीं है बहस का।' कहकर वे खिसक लीं।

मेरे साथ एक बार नहीं बार बार ऐसा हुआ है। केवल श्रीमती ही नहीं तो अड़ोसी-पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे तो बच्चे, दफ्तर के सहकर्मी तक मानों मौका खोजते ही रहते हैं।

एक बार नया सूट सिलवाया, रंग और डिजाइन श्रीमती के पसंद की, बच्चों की पसंद का टेलर। कहने को अब अपनी पसंद का अब रहा ही क्या? फिर भी सहकर्मियों ने कहा, ये कहाँ से सिलवा लिया?

रंग तुम पर जँच नहीं रहा। किसी ने कहा। तीसरा बोला- 'ये बहुत पुरानी फैशन का है।

जिस उत्साह और आनंद से सूट सिलवाया था, वह अब अलमारी की शोभा बढ़ा रहा है।

जिंदगी में ऐसे तमाम अवसर आते हैं, जब आप अपनी खुशियाँ, अपने सुख किसी और के साथ बाँटने को तत्पर होते हैं, परंतु उनके पास इस खुशी को मनाने का कोई कारण नहीं होता। सच में तो दूर की बात है, वे झूठ-मूठ भी आपकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। न करें, पर सामने वाले की खुशी में अपनी तत्परता का जामन लगाकर दही तो न करें। पर ऐसा नहीं होता।

अब मेरे बचपन का ही किस्सा लें। परीक्षा में कभी ऐसे नंबर नहीं आए कि मैं उनकी खुशी मना सकूँ। एक बार मौका मिला भी तो पड़ोसी के बच्चे ने आकर खुशी से फूले मेरे गुब्बारे हवा निकाल दी। अंकल मेरे तो बांसठ प्रतिशत बने।

और इसके तिरसठ। पर पिता के बोलने के तरीके में ही ताना था। खुशी नहीं - आखिर स्कूल में और घर में करता क्या है? पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करते हो? तुम्हारे पास और काम भी क्या है? उसे देख, बासठ प्रतिशत लाया, बासठ। ये बात और थी कि उन्हें और मुझे बड़ी देर बाद समझ आया कि तिरसठ प्रतिशत अंक याने बासठ से हमेशा ज्यादा ही होते हैं। पर उन्हें तब मेरी सफलता देखी गई हो तब न? इस चक्कर में तो वे अपने हाथ पहले ही मुझ पर साफ कर गये।

कहाँ पुरानी बातें ले कर बैठ गया।

इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर किसी को भी किसी और की खुशी से कोई मतलब नहीं है। जबकि हर कोई इस कोशिश में है कि वह कुछ ऐसा करें कि कोई कहे कि वह उसकी खुशी में शामिल हैं।

ट्रंप साहब, लाख दावे करें, कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम उन्होंने कराया, पर भारत मानने को तैयार नहीं। यदि चार लोग यही कह देते तो किसी का क्या जाता कि हाँ, ट्रंप के कहने से ही युद्ध विराम हुआ, तो एक नोबल, ट्रंप साहब की झोली में आ गिरता।

पाकिस्तान यह बताकर खुशी होना चाहे कि आपरेशन सिंदूर में उसने भारत को हराया तो बाकी कोई मानने को तैयार नहीं। मोदीजी यह लाख कहें कि हमने देश को विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया पर विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं।

मजे की बात तो यह है कि हमारे उत्सवों पर भी हमेशा एक उंगली, उठी रहती है। दीपावली पर पटाखे क्यों? होली पर पानी का नुक़सान क्यों? नये साल पर धूम धड़ाका, मस्ती, नाच, नशा, हम करें तो पुलिस और परंपरावादियों के पेट में दर्द हो। यह तो कोई बात नहीं हुई।

साहब यह दुनिया ऐसी ही है। हर स्त्री, माँ नहीं होती, हर पुरुष दोस्त नहीं होता। जो आपकी खुशी में खुश हो लें। हर किसी को आपकी खुशफहमी बर्दाश्त नहीं होती।

पर्यावरण

सुरेश उपाध्याय

लेखक स्तंभकार हैं।

रस्म अदायगी न बने आबोहवा की फिक्र

जब हवा और पानी से डर लगने लगे तो थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते थे और कहां आ गए है. विकास के नाम पर हमने जो रास्ता चुना उसने हमें विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है. नदी, बावड़ी, कुओं, तालाबों आदि प्राकृतिक जल स्त्रोतों को अतिक्रमण, सीवरेज व औद्योगिक अपशिष्ट से संकुचित, प्रदुषित कर उपयोग के लिए अप्रयुक्त बनाया या विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है. वनों व वृक्षों की कटाई ने हरितिमा के साथ प्राण वायु को लील लिया है. उद्योग की विषैली गैसें वातावरण को दूषित कर रही हैं. वायु प्रदुषण ने सांसों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. पहाड़ों पर चौड़ी सड़कों व बांधों ने अलग संकट खड़े कर दिए है. जलजनित व वायुजनित बीमारियों ने जनजीवन को संकट में तो डाला ही है, चिकित्सा सुविधाओं के व्यवसायीकरण ने परिवारों को आर्थिक संकट में उलझा दिया है. बेतरतीब बरसात, बढ़ता तापमान व लम्बी अवधि की गर्मी इस संकट के प्रमाण है. पर्यावरण नियमों व कानूनों की अनदेखी / अवहेलना की जा रही है. किसी को इन नियमों / कानूनों के अनुपालन की चिंता नहीं है और जिम्मेदारी व जवाबदेही जैसे शब्द अपना वजूद खो चुके हैं.

हवा और पानी जीवन के आधार हैं तथा आज विकास के तमाम दावों और वादों के बीच इनकी उपलब्धता, शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर गम्भीर संकट आसन्न है. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक मासूम सहित इक्कीस नागरिकों की मौत तथा सैंकड़ों के अस्वस्थ होने की घटना ने स्तब्ध कर दिया है. इसकी सुर्खियां बनी हुई है और इसी बीच सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट ने खौफ का विस्तार कर दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 4041 में से 1787 शहर गम्भीर वायु प्रदुषण के शिकार हैं. देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक प्रदुषित शहरों में से एक है तथा प्रतिवर्ष नागरिक जीवन के समक्ष जो जटिल स्थितियां निर्मित होती है, उससे सभी वाबस्ता हैं.

जब हवा और पानी से डर लगने लगे तो थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते थे और कहां आ गए है. विकास के नाम पर हमने जो रास्ता चुना उसने हमें विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है. नदी, बावड़ी, कुओं, तालाबों आदि प्राकृतिक जल स्त्रोतों को अतिक्रमण, सीवरेज व औद्योगिक अपशिष्ट से संकुचित, प्रदुषित कर उपयोग के लिए अप्रयुक्त बनाया या विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है. वनों व वृक्षों की कटाई ने हरितिमा के साथ प्राण वायु को लील लिया है. उद्योग की विषैली गैसे वातावरण को दुषित कर रही है. वायु प्रदुषण ने सांसों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है. पहाड़ों पर चौड़ी सड़कों व बांधों ने अलग संकट खड़े कर दिए है. जलजनित व वायुजनित बीमारियों ने जनजीवन को संकट में तो डाला ही है, चिकित्सा सुविधाओं के व्यवसायीकरण ने परिवारों को आर्थिक संकट में उलझा दिया है. बेतरतीब बरसात, बढ़ता तापमान व लम्बी अवधि की गर्मी इस संकट के प्रमाण है. पर्यावरण नियमों व कानूनों की अनदेखी / अवहेलना की जा रही है. किसी को इन नियमों / कानूनों के अनुपालन की चिंता नहीं है और जिम्मेदारी व जवाबदेही जैसे शब्द अपना वजूद खो चुके हैं.

चमचमाती फोरलेन / सिक्सलेन सड़कों, मल्टीलेयर फ्लायओवर, माल व तथाकथित आधुनिक जीवन शैली की चकाचौंध में जीवन के आधार तत्वों के प्रति घोर लापरवाही ने जनजीवन के सामने जो संकट खड़े किए हैं, वह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है. मानव निर्मित इन खतरों के संकेतों को पढ़ने, समझने व उस पर गम्भीरता से चिंतन व मनन की जरुरत है. अल्पकालीन व दीर्घकालीन स्तर पर दो तरह की नीतियों व कार्यक्रमों पर विचार - विमर्श की जरुरत है. अल्पकालीन नीतियों व कार्यक्रमों में उपलब्ध संसाधनों के समुचित, समंवित, सुव्यवस्थित व समावेशी वितरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. दीर्घकालीन नीतियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन के उपाय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. नदियों, तालाबों, कुओं का पुनर्जीवन करने के लिए उनकी सफाई ही पर्याप्त नहीं है. उनके सीमांकन के साथ उनके व केचमेंट एरिया के अतिक्रमण हटाने होंगे तथा सीवरेज व उद्योगों के अपशिष्ट को मिलने से रोकना ही होगा. नदियों के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध व साफ करने का विचार निरर्थक है. नदियों को उनका प्राकृतिक स्वरुप व सौंदर्य लौटा दीजिए वे अपनी सफाई स्वयं कर लेगी.

इंदौर के भागीरथपुरा का संकट इसलिए अधिक गम्भीर संकेतक है कि इस शहर को प्रदेश की आर्थिक व व्यवसायिक राजधानी कहा जाता है, देश में आठ मर्तबा सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल है, स्मार्ट सिटी में इसका चयन किया गया है तथा वाटर प्लस का तमगा भी मिला हुआ है. घोर लापरवाही, संवेदनहीनता की इस घटना को सिस्टम (प्रणाली) का दोष बताकर व्यक्तिगत जवाबदेही से छूट का रास्ता निकालना ही कहा जा सकता है. सिस्टम (प्रणाली) लोगों को कार्य की जिम्मेदारी व इसका निर्वाह नियम / कानून के अनुसार करने का ही नाम है. इतनी जघन्य घटना में एक दो का निलम्बन व स्थानांतरण लीपापोती व आक्रोश को कम करने का प्रयास ही कहा जा सकता है. जिनके परिजन इस घटना में गुजरे हैं, उनके दर्द व पीड़ा को महसूस करने की जरुरत है, आर्थिक सहायता को मौत का मुआवजा मानना / कहना निकृष्टतम सोच होकर निंदनीय है.

शहर के मास्टर प्लान कागजी कार्रवाई बन कर रह गए हैं, समय पर न प्लान तैयार होते हैं न उनका क्रियान्वयन ठीक से होता है. शहर की बुनियादी जरुरतों की पूर्ति नहीं हो रही है और उनका अनावश्यक विस्तार किया जा रहा है. अवैध कालोनियों व निर्माणों का काम बेरोकटोक जारी है. शहर के मास्टर प्लान के साथ पानी (पेय व उपयोगी), सीवरेज व हरियाली का भी मास्टर प्लान बनाना जरुरी है. इनके क्रियान्वयन की एजेंसियों में समन्वय जरुरी है अन्यथा सिवरेज वाले पानी के तथा पानी वाले सिवरेज के पाइप में तोड़फोड़ करते रहेंगे तथा जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहेंगे और सिस्टम की खामी बताकर व्यक्तियों को बचाते रहेंगे. पानी का कारोबार तो बढ़ ही रहा है, भागीरथपुरा जैसी घटनाएं उसके लिए बुस्टर डोज का काम करेगी तथा अभी नहीं चेते तो सम्भव है निकट भविष्य में शहरों में भुगतान पर आक्सीजन बूथ की सेवाएं प्रारम्भ हो जाएगी.

आबोहवा की फिक्र मनुष्य, प्राणी व वनस्पति जगत के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है. धीमी मौतों व गम्भीर रोगों के लिए यह प्रीवेंटिव ट्रीटमेंट (निवारक उपचार) है. यह फिक्र रस्म अदायगी बन कर न रह जाए, वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए यह हमारा कर्तव्य भी है तथा धर्म समझे तो धर्म भी है.

जंगल सफारी

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं!

वन्यजीवों से उनके घर आंगन में मिलने का सुख

पर्यटक और ट्रैवेलर्स अक्सर अपनी यात्रा में जंगल सफारी को भी शामिल करते हैं और उस क्षेत्र के खास प्राणियों को देखने की योजना बनाते हैं। जंगल सफारी न केवल रोमांच का अनुभव कराती है, बल्कि हमें प्रकृति और वन्यजीवों के करीब आने का मौका भी देती है। हमने अनेक ट्रेवलरों को उनके बनाए वीडियोस में यूट्यूब पर दुनियाभर के अभ्यारण्यों और नेशनल पार्कों में जंगल सफारी का आनंद लेते देखा है। हाल ही में अफ्रीका के विभिन्न अभयारण्यों में वन्य जीवों को बिल्कुल नजदीक से देखते हुए रोमांचित हुए। खासतौर से जेबरा,जिराफ, हाथियों और शेर आदि को समूहों में विचरण करते देख बहुत आनंद की अनुभूति होती है।

कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य सफारी के लिए ऐसे स्थान हैं जिन्हें 'स्वर्ग' माना जा सकता है इनमें से अफ्रीका का मसाई मारा नेशनल रिजर्व, केन्या यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सफारी जगहों में से एक है। यहाँ 'द बिग फाइव' (शेर, तेंदुआ, हाथी, भैंसा और गैंडा) पाए जाते हैं। मुख्य आकर्षण यह देखना है जब 'ग्रेट माइग्रेशन' (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान जहाँ लाखों की संख्या में ज़ेबरा और वाइल्डबीस्ट नदी पार करते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क एक और अफ्रीका का सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्यानों में से एक है। यहाँ आप स्वयं कार चलाकर (Self-drive safari) भी अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी जंगली कुत्ते और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां का आनंद ले सकते हैं। नेशनल पार्क के गाइड और वाहनों से भी ये सफारी की जा सकती है, जो सुरक्षित होती है। ये खास गाड़ियां वन्य जीवों के बिल्कुल नजदीक तक ले जाकर ट्रैवलरों, पर्यटकों को जानवरों की गतिविधियों का दर्शन कराते हैं।

यदि दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के ऐसे जानवरों की बात करें जो केवल उन्हीं क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं और वहां की पहचान कहे जा सकते हैं तो इसे जानना भी बड़ा रोचक होगा। अफ्रीका महाद्वीप से ही बात शुरू करते हैं। अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाए जाने वाले सिंह याने शेर दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में से एक हैं। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले हाथी डायनासोर के खत्म हो जाने के बाद जमीन पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं। दुनिया के सबसे लंबे जानवर जिराफ भी यहीं के मैदानों में पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले अपनी विशिष्ट धारियों से मन मोहने वाले जेब्रा भी अफ्रीका की खास पहचान हैं। यहां की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले हिप्पोपोटेमस दुनिया के सबसे बड़े जलीय जानवरों में से एक हैं। कैंपफायर नामक बर्डअफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाए जाने वाले पक्षी अपनी विशिष्ट आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले चिम्पैंजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक होते हैं। इस धरती पर जीवन और जीवों की उत्पत्ति भी अफ्रीका से शुरू होना माना गया है। आधुनिक मनुष्य भी यहीं से निकली एक प्राणी प्रजाति है।

गोरिल्ला भी जंगलों में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी प्राणी हैं। घास के मैदानों में पाए जाने वाले यहां के लेपर्ड अपनी विशिष्ट धारियों के लिए जाने जाते हैं। यहां आए पर्यटकों को जब विशिष्ट सिंग वाला राइनो (गेंडा) दिख जाता है तो उसकी सफारी का आनंद द्विगुणित हो जाता है। वैसे यदि अफ्रीका के दो बेहद आकर्षक जीवों की बात करें तो सबसे पहले जिराफ और जेब्रा की तस्वीर ही मन में उभर जाती है।

अफ्रीका में जिराफों की विभिन्न प्रजातियां केन्या और तंजानिया में यहाँ 'मसाई जिराफ' भारी संख्या में पाए जाते हैं। घास के मैदानों में इन्हें झुंड में चलते देखना एक क्लासिक सफारी अनुभव होता है।

सम्बुरु नेशनल रिजर्व, केन्या में दुर्लभ 'रेटिकुलेटेड जिराफ' पाए जाते हैं, जिनके शरीर पर गहरे भूरे रंग के सुंदर चौकोर निशान होते हैं। मर्चिसन फॉल्स, युगांडा में 'रॉथ्सचाइल्ड जिराफ' की सबसे बड़ी आबादी रहती है। जिराफ दुनिया के सबसे ऊँचे स्तनधारी जीव हैं। वे खड़े-खड़े ही सोते हैं और उनकी जीभ लगभग 21 इंच लंबी और नीले-काले रंग की होती है, जो उन्हें ऊँचे काँटेदार पेड़ों की पत्तियाँ खाने में मदद करती है।

क्रूगर नेशनल पार्क में आप अपनी गाड़ी से भी सफारी कर सकते हैं और 'साउथ अफ्रीकन जिराफ' को करीब से देख सकते हैं। नैरोबी का जिराफ मैनर एक अनूठा होटल है जहाँ जिराफ को ऊंची बालकनी से अपने हाथों से नाश्ता करवाया जा सकता है।

भारत के जंगलों में जिराफ नहीं होते हैं, यद्यपि जीवों को अन्य स्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित करना संभव है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवों की विशिष्ट प्रजातियाँ विशिष्ट जलवायु, मिट्टी, और पर्यावरणीय स्थितियों में विकसित9 होती हैं, इसलिए उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना आसान नहीं होता है। लेकिन देश के कुछ प्रमुख चिड़ियाघरों में इन्हें देखा जा सकता है। मैसूर चिड़ियाघर (कर्नाटक) को जिराफों का सबसे अच्छा प्रजनन केंद्र माना जाता है। अलीपुर चिड़ियाघर (कोलकाता) में भी जिराफों की अच्छी संख्या है। पटना चिड़ियाघर (संजय गांधी जैविक उद्यान) बिहार भी चिड़ियाघर जिराफों के लिए काफी लोकप्रिय है। खबर है कि वन विहार नेशनल पार्क (भोपाल) में जिराफ और ज़ेबरा लाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि पर्यटक इन्हें देख सकें। चिड़ियाघर में वन्य जीवों के देखने में वह मजा उतना नहीं जो उन्हीं के घर में ,उन्हीं के आंगन में स्वछंद निर्भीक विचरण करते उन्हें देखने में हमे आ पाता है।

प्रतिक्रिया

अरूण कुमार डनायक

लेखक भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत सहायक महाप्रबंधक हैं ।

भारत में श्रमिक आंदोलन और हड़तालों का बदलता परिदृश्य

23 सितंबर 1954 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर भारत में पहली अखिल भारतीय बैंक हड़ताल हुई। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार का लेबर अपीलीय न्यायाधिकरण (शास्त्री अवॉर्ड) के वेतन निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रयास था, जिससे कर्मचारियों को लगा कि सामूहिक सौदेबाजी और संस्थागत न्याय कमजोर किया जा रहा है। इस असहमति के चलते तत्कालीन श्रम मंत्री वी. वी. गिरी ने इस्तीफा दे दिया। यह घटना न्यायिक निर्णयों और श्रमिक हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता और भारतीय श्रमिक आंदोलन में संस्थागत स्वतंत्रता और सामूहिक संघर्ष की महत्वता को दर्शाती है। इसके बाद 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल ने वेतन, पदोन्नति और सेवाशर्तों में सुधार कर बैंकिंग यूनियनों को निर्णायक शक्ति दी और देसाई अवॉर्ड को प्रेरित किया।

अजय बोकिल ने 'सुबह सवेरे' में 7 जनवरी 2026 को प्रकाशित अपने आलेख में गिग वर्कर्स की कठिन परिस्थितियों को बारीकी से उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि ऐप आधारित डिलीवरी और कैब सेवाओं में लगे युवा, स्वतंत्र ठेकेदार होते हुए भी कंपनियों और ग्राहकों के दबाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बोकिल का यह आलेख श्रमिकों की वास्तविक स्थिति और आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में हड़ताल की कमजोर होती शक्ति को समझने के लिए अत्यंत मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास समृद्ध और निर्णायक रहा है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, रेलवे और बड़े निजी उद्योगों में संगठित आंदोलन न केवल वेतन और सेवा शर्तों में सुधार लाए, बल्कि औद्योगिक संबंधों की दिशा भी निर्धारित की।

23 सितंबर 1954 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर भारत में पहली अखिल भारतीय बैंक हड़ताल हुई। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार का लेबर अपीलीय न्यायाधिकरण (शास्त्री अवॉर्ड) के वेतन निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रयास था, जिससे कर्मचारियों को लगा कि सामूहिक सौदेबाजी और संस्थागत न्याय कमजोर किया जा रहा है। इस असहमति के चलते तत्कालीन श्रम मंत्री वी. वी. गिरी ने इस्तीफा दे दिया। यह घटना न्यायिक निर्णयों और श्रमिक हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता और भारतीय श्रमिक आंदोलन में संस्थागत स्वतंत्रता और सामूहिक संघर्ष की महत्वता को दर्शाती है। इसके बाद 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल ने वेतन, पदोन्नति और सेवाशर्तों में सुधार कर बैंकिंग यूनियनों को निर्णायक शक्ति दी और देसाई अवॉर्ड को प्रेरित किया।

भारतीय रेल में 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई। लगभग 17 लाख कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, बोनस, आठ घंटे की ड्यूटी और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग की। सरकार की कड़ी दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद यह हड़ताल भारतीय राजनीति और श्रमिक इतिहास की एक युगांतकारी घटना बनी और आगे चलकर आपातकाल की पृष्ठभूमि भी तैयार की।

मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व के समय कोयल मजदूरों की हड़ताल सरकारी दमन और राजनीतिक समर्थन के अभाव का शिकार हुई।

निजी क्षेत्र में श्रमिक संघर्ष अपेक्षाकृत असुरक्षित रहे हैं। 2012 में मारुति सुजुकी, मानेसर में यूनियन मान्यता, अनुबंध प्रथा और कार्य परिस्थितियों को लेकर तनाव हिंसक रूप ले गया, जिससे एक प्रबंधक की मृत्यु हुई। परिणामस्वरूप कई कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया । कठोर न्यायिक दंड लागू होने से निजी उद्योगों में संगठित आंदोलन हतोत्साहित हो गए।

दत्ता सामंत के नेतृत्व में 1982 की मुंबई और 1977-78 की कानपुर मिल हड़ताल ने दिखाया कि लंबा संघर्ष पूरे उद्योग के पतन और बेरोजगारी का कारण बन सकता है।

उदारीकरण के बाद भारत में श्रमिक आंदोलन फीका पड़ गया। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में अस्थायी रोजगार बढ़े, जिससे हड़ताल की सामूहिक शक्ति कमजोर हुई। महँगी शिक्षा और छात्रों का कर्ज भी युवाओं को अस्थायी, जोखिमपूर्ण रोजगार स्वीकारने पर मजबूर करता है। सरकारी श्रम कानूनों और नीतिगत बदलावों ने इस प्रवृत्ति को और बल दिया; आर्थिक सुधारों का लक्ष्य निवेश और लचीलापन था, जिससे श्रमिक संरक्षण की मूल भावना धीरे-धीरे कमजोर हुई और हड़तालें अप्रभावी हो गई ।

श्रम कानूनों में नए बदलावों के बाद श्रमिक आंदोलन पर तीन प्रमुख प्रभाव पड़े। सबसे पहले, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग और अस्थायी नियुक्तियों से नौकरी की स्थायित्व कम हुई, जिससे यूनियनों की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ी और आंदोलन में भाग लेना जोखिमपूर्ण हुआ। दूसरा, एसमा का व्यापक उपयोग, लंबी नोटिस अवधि और हड़तालों को अवैध ठहराने की प्रवृत्ति ने आन्दोलन के मौलिक अधिकार को सीमित किया। तीसरा, 2020 की चार श्रम संहिताओं और 2025 के शीतकालीन सत्र में पारित नए कानूनों ने नियोक्ताओं को 'हायर एंड फायर' में अधिक लचीलापन दिया, जबकि ट्रेड यूनियनों की मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया जटिल बना दी। इन बदलावों ने संगठित विरोध की संभावना और पारंपरिक हड़तालों की शक्ति दोनों को कमजोर किया।

बैंकिंग क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन के क्षीण होने में केवल परिस्थितियाँ ही नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनाई गई प्रबंधकीय रणनीतियाँ भी प्रमुख रही हैं। प्रबंधन ने 'पेशेवर' रुख अपनाते हुए श्रमिक प्रश्न को मानवीय विमर्श से हटाकर मात्र प्रदर्शन और लक्ष्य की भाषा में सीमित कर दिया। यूनियन में सक्रिय कर्मचारियों की दूरस्थ स्थानों पर तैनात करना और अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति उन्हें श्रमिक समुदाय से वैचारिक रूप से अलग कर देता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बंद कर यूनियनों की रीढ़ कमजोर कर दिया गया । साथ ही, तकनीकी हस्तक्षेप और स्वचालन ने मानवीय भूमिका सिकोड़कर सामूहिकता और सौदेबाजी–दोनों की शक्ति को कमजोर कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और डर के माहौल ने हड़ताल में भाग लेने की हिम्मत भी कम कर दी, जिससे बैंकिंग क्षेत्र का श्रमिक आंदोलन प्रतिरोध से हटकर समायोजन और मौन की राजनीति में बदल गया।

बेहतर वेतन और करियर अवसरों ने कर्मचारियों के एक हिस्से को सामूहिक संघर्ष से विमुख किया, जबकि स्थायी नियुक्तियों में गिरावट से यूनियन सदस्यता घटी। परिणामस्वरूप बार-बार की बैंक हड़तालें उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक बनीं और सामाजिक समर्थन धीरे-धीरे कम होता गया।

संसद में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व घटने से श्रमिक हितों पर बहसें भी सीमित होती चली गईं। हड़तालों और आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण और वैचारिक समर्थन मिलना कम हो गया। राजनीतिक दलों ने श्रमिक नेताओं को चुनावी राजनीति से दूर रखा, जिससे ट्रेड यूनियन नेतृत्व और संसदीय प्रक्रिया के बीच कड़ी टूट गई। निवेश-अनुकूलता के नाम पर श्रम सुधारों की बहस औपचारिकता बन गई, और हड़ताल जैसा अहिंसक साधन प्रायः निष्प्रभावी प्रतिरोध रह गया।

स्वतंत्र भारत के संगठित श्रमिक आंदोलन से गिग अर्थव्यवस्था तक की यह यात्रा केवल आर्थिक बदलाव की नहीं, बल्कि श्रमिक शक्ति, न्याय और संरक्षण के लगातार सिमटते दायरे की कहानी है। कर्मचारी संघों और नेताओं के उत्पीड़न और सरकारी दमन के बावजूद ऐतिहासिक हड़तालों ने वेतन, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी, किंतु उदारीकरण, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और नई श्रम संहिताओं ने सामूहिक प्रतिरोध को क्रमशः कमजोर किया। आज गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों की असुरक्षा यह दर्शाती है कि नीतिगत प्राथमिकताएँ अक्सर श्रम के बजाय बाज़ार के पक्ष में झुकी रहीं। ऐसे में गांधीजी द्वारा 'यंग इंडिया' (11 फरवरी 1920) में प्रतिपादित न्यूनतम मानवीय मानक–उचित कार्य घंटे, शिक्षा, स्वच्छ आवास और बुढ़ापे की सुरक्षा–आज भी याद दिलाते हैं कि श्रम केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा का मूल प्रश्न है।

Mantra of success

राजेश शर्मा
सीनियर जर्नलिस्ट,
मोटिवेशनल स्पीकर

गर स्वप्न आसमां की तरह बड़े हों, तो उड़ान भी उतनी ही ऊंची होगी

आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत इस युवा संभावनावान, प्रतिभाशाली बिटिया ने अपनी प्रतिभा और संभावनाओं के दर्शन करा दिए थे कि एक दिन यह प्रतिभा अपनी उजास की चमक बिखेरेंगी ... मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं में टापर रह कर डिप्टी कलेक्टर बनी हर्षिता दवे ने जता दिया कि बेटियां आज हर दिशा में अपनी बुलंदियों का परचम फहरा रही है। नींव से नभ तक बेटियों की उड़ान बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बयां कर रही है ।

कॉलम 'Mantra of success' के लिए राजेश शर्मा से खास चर्चा में हर्षिता दवे ने दिए मोटिवेशनल मंत्र-

राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय डिबेट - भाषण प्रतियोगिता की यात्रा से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफर कैसे हासिल किया ?

हर्षिता दवे : मुझे स्कूल के दिनों से ही डिबेट और भाषण में रुचि थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि राष्ट्रीय युवा उत्सव के मंच पर जीत हासिल कर अंतरराष्ट्रीय युवा उत्सव जैसे मंच पर भाग लेने का अवसर मिला। लेकिन 20 साल की उम्र में मंच से कुछ समय के लिए दूरी बना ली और पीएससी की तैयारी शुरू की। सौभाग्य से 2024 की परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ। यह पूरी यात्रा अनेक नए अनुभवों, नई सीख और नई ज़िम्मेदारियों से भरी रही।

युवाओं को जीवन को संवारने, खासकर करियर में आगे बढ़ने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी ?

हर्षिता दवे : मुझे लगता है हर व्यक्ति की परिस्थिति और व्यक्तित्व अलग है इसलिए हर व्यक्ति अपना जीवन स्वयं ही संवार सकता है। चाहे कोई भी करियर हो बस परिश्रम से मत घबराइए और स्वयं पर

विश्वास रखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। बस यही कहूंगी करियर का चुनाव हमेशा अपने व्यक्तित्व और कौशल के अनुरूप कीजिए, किसी और से प्रभावित होकर नहीं।

आज यूथ निराश हैं - तनाव से भरा और कुंठित हैं। निराशा के भंवर में आप क्या संदेश देना चाहेंगी ?

हर्षिता दवे : दरअसल युवावस्था कई सारे उतार-चढ़ाव और सफलता- असफलता से भरी है इसलिए कभी निराशा होना तो कभी उत्साहित होना स्वाभाविक है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 200 प्रतिशत दें, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। बस याद रखें मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है। निराशा से बाहर निकलने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करें, मेडिटेशन करें और अपने लिए समय निकालें।

दुनिया में भारत यूथ पावर का एक बड़ा केंद्र बन रहा है आप कैसे देखती हैं भारत और भारतीयों की ताकत को ?

हर्षिता दवे : बिल्कुल, युवा शक्ति भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान है। जिस देश में इतनी अधिक युवा आबादी हो उस देश में उतना ही अधिक नवाचार, उतनी ही अधिक ऊर्जा और उतनी ही अधिक रचनात्मकता होगी। बस आवश्यकता है युवाओं को सही दिशा और दशा प्रदान करने की।

हर्षिता ने यूथ को मोटिवेट करने के लिए यह पंक्तियां साझा की...

'तुम पिंजरे के पंछी नहीं, तुम आसमां के परिंदे हो।
तुम सहमी सी नदी नहीं, तुम सागर की तरंगे हो।
तुम मांझे की पकड़ नहीं, तुम लहराती पतंगे हो।
और तुम परतंत्रता की नहीं, बल्कि आज़ाद भारत की आज़ाद उमंगे हो।'

नागरिक लगा रहे नपा के चक्कर, पोर्टल कब शुरू होगा, अधिकारी भी नहीं दे पा रहे जवाब

बीपीएल का सत्यापन बंद, परेशान हो रहे नागरिक

एस. द्विवेदी, बैतूल। बीपीएल के सत्यापन का पोर्टल करीब ढ़ाई महीने से बंद है। जिसके कारण लोग परेशान है। हितग्राही सत्यापन के लिए रोजाना नगरपालिका के चक्कर काट रहे है, लेकिन पोर्टल बंद होने से बीपीएल का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। हालांकि पोर्टल कब तक शुरू होगा, इस संबंध में अधिकारी भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में बीपीएल के सत्यापन का पोर्टल बंद है। कब तक शुरू होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दे कि राशन दुकानों से खाद्यान्न लेने के लिए सबसे जरुरी बीपीएल का सत्यापन होता है। सत्यापन के बाद ही फूड कूपन मिलता है और राशन शुरू होता है। लेकिन बीपीएल सत्यापन का कार्य ही अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इससे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। सत्यापन के अभाव में उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। बता दे कि इस साल शासन द्वारा ई-केवायसी कराई गई थी, ताकि पात्र लोग ही निःशुल्क राशन ले सके। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसे लोगों की सूची राज्य शासन को भिजवाई गई थी, जिनका टर्न ओवर काफी ज्यादा है, लेकिन उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल हैं और वे राशन भी ले रहे हैं। बताया जाता है कि इन दोनों ही आधार पर केवल बैतूल शहर के ही करीब 4900 लोगों के राशन कार्ड

निरस्त हुए हैं।

सत्यापन के लिए नपा आते थे आवेदन

ई-केवायसी नहीं होने और अन्य कारणों से नाम कटने के कारण 4900 लोगों के राशन कार्ड निरस्त हो गये। इन्हें शासन से जो राशन मिलता था, वह भी बंद हो गया। जिससे ऐसे लोगों में हड़कम्प मचा हुआ है। ऐसे लोग दोबारा नाम जुड़वाने और राशन शुरू करवाने के लिए आवेदन देने लगे। खाद्य विभाग और एसडीएम ऑफिस में आवेदन दिए जाने पर वहां से बीपीएल सत्यापन के लिए नगर पालिका भिजवाया जाता है। इधर नगरपालिका से करीब 500 लोगों के सत्यापन किए गए, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर से बीपीएल का सत्यापन का कार्य बंद कर हो गया है। नगरपालिका में इस संबंध में सूचना चस्पा कर दी गई है कि पोर्टल बंद होने से का कार्य अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है।

इनका कहना है -

शासन से ही बीपीएल के सत्यापन का पोर्टल बंद है। जिसके कारण सत्यापन नहीं हो पा रहा है। पोर्टल कब शुरू होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। करीब 200 से 300 आवेदन सत्यापन के लिए पेंडिंग पड़े हुए है।

- **अविनाश भाटिया,** नगरपालिका बैतूल

सत्यापन के 200 से 300 आवेदन पेंडिंग

पोर्टल बंद होने से अब सत्यापन के लिए जहां नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं पूर्व में लिए जा चुके करीब 200 से 300 आवेदन भी पेंडिंग में पड़े हैं। सत्यापन का यह कार्य कब से शुरू होगा, इसे लेकर अधिकारी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सत्यापन का पोर्टल केवल बैतूल में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में ही बंद पड़ा है। सत्यापन का कार्य बंद होने के कारण बैतूल शहर ही नहीं पूरे जिले में हजारों लोग खासे परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों के नाम विभिन्न कारणों से कट चुके हैं, उनका सत्यापन होकर दोबारा नाम नहीं जुड़ पा रहा है। इससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा नए सदस्यों के नाम भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कई गरीब परिवार भी इस कारण से खासे परेशान हो रहे हैं।

जिले में 3 लाख से अधिक परिवारों को मिलता है राशन

जिले में 3 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिमाह राशन मिलता है। इन परिवारों में 29 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग शामिल है। जिसमें बीपीएल कार्डधारी भी है। लेकिन अब बीपीएल का सत्यापन नहीं होने से न तो कटे हुए नाम जुड़ पा रहे है और न ही नये नाम जुड रहे है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है, जिनके नाम किसी कारण से राशन की पात्रता सूची से हट गये है, लेकिन वे पात्रता रखते है। ऐसे लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए परेशान हो रहे है। नपा के अविनाश भाटिया ने बताया कि रोजाना 10 से 12 लोग बीपीएल के सत्यापन के लिए नगरपालिका आते है, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

जिला आयुष कार्यालय में सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा

अधिकारियों ने की औषधि वितरण की जांच

बैतूल। संचालनालय आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेशानुसार सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर जिला आयुष कार्यालय बैतूल में बैठक आयोजित की गई। इसके पूर्व 13 जनवरी को जिला आयुष अधिकारी बैतूल डॉ. योगेश चौकीकर द्वारा जिला आयुष कार्यालय नर्मदापुरम में निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला आयुष अधिकारी नर्मदापुरम श्री श्रीराम कनोजिया एवं उनकी टीम ने सिकल सेल एनीमिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान नर्मदापुरम जिले में सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त रोगियों की सूची एवं समस्त अभिलेखों का सूक्ष्म और विस्तृत निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में 14 जनवरी को जिला आयुष कार्यालय बैतूल में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला आयुष अधिकारी विदिशा डॉक्टर दिनेश अहिरवार द्वारा बैतूल जिले के कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में सिकल सेल एनीमिया रोगियों की सूची, अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा रोगियों से दूरभाष एवं घर-घर संपर्क कर औषधि वितरण की जानकारी लेकर पुनः परीक्षण किया गया। बैठक में जिला आयुष अधिकारी डॉ.योगेश चौकीकर के साथ डॉक्टर अमृत राव बर्डे, नोडल अधिकारी डॉक्टर सरिता डेहरिया, डॉक्टर अजय मांडवे, डॉक्टर अतुल राय, डॉक्टर विशाल वर्मा एवं डॉक्टर मनोज सूर्यवंशी उपस्थित रहे। आयुक्त के आदेशानुसार सिकल सेल एनीमिया में एड ऑन थेरेपी के रूप में आयुष औषधि वितरण के निर्देश प्राप्त हुए। जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय बैतूल की अध्यक्षता में सिकल सेल एनीमिया समन्वय समिति का गठन किया गया। इसके तहत आयुष विभाग द्वारा सिकल सेल यूनिट बनाई गई, जिसकी नोडल अधिकारी डॉक्टर सरिता डेहरिया को नियुक्त किया गया। बैतूल जिले के समस्त 10 ब्लॉक में चिकित्सा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। सीएमएचओ बैतूल से प्राप्त सूची के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से चिन्हित रोगियों को घर-घर जाकर आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। 10 से 13 नवंबर तक विशेष शिविर आयोजित कर 722 रोगियों को औषधि दी गई तथा 18 नवंबर को गर्भवती सिकल सेल रोगियों हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। भीमपुर एवं भैंसदेही ब्लॉक में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति कर लक्ष्य पूर्ण किया गया।

धाबा में आदिवसियों, दलितों के लिए बना स्कूल भवन तोड़ने पर संगठन और सजप ने जताया रोष

बैतूल। भैंसदेही तहसील के पंचायत एवं ग्राम धाबा में गाँव के आदिवासी व दलित बच्चों हेतु नईम खान द्वारा अपनी निजी जमीन पर 20 लाख से बनाए गए स्कूल भवन पर प्रशासन व्दारा बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई का श्रमिक आदिवासी संगठन एवं समाजवादी जन परिषद ने कड़ा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह स्कूल एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनाया है, इसलिए मदरसा करार देकर तोड़ना सरासर गलत है। सजप के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र गढवाल ने कहा कि जहां सरकार उनकी लगातार मांग के बावजूद दानवाखेडा, भंडारपानी जैसे कईयों गांवों में स्कूल नहीं खोल पा रही है। वहीं कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर अपने पैसे से स्कूल भवन बना रहा है तो उसे सरकार कुछ लोगों की गलत शिकायत पर गैर कानूनी बताकर तोड़ रही है। सजप के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य एवं होशंगाबाद जिले के आदिवासी नेता फागराम सेलू ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पडे। हरदा जिले के पूर्व जनपद सदस्य रामदीन टेकाम ने कहा कि इस घटना के विरोध में जरुरत पडने वो सड़क पर उतरेंगे। अनुराग मोदी ने कहा कि पंचायत ने 11 जनवरी 2026 को नईम को नोटिस दिया और 12 जनवरी को जिला प्रशासन ने स्कूल भवन तोडने की कार्रवाई कर दी। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लघंन है। इसमें दोषी अधिकारियो पर कार्रवाई होना चाहिए। वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। यहां उल्लेखनीय है कि बुलडोजर कार्रवाई या बुलडोजर जस्टिस के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय (नवम्बर 2024) दे चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को गिरा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी भवन को ढहाने से पहले संबंधित व्यक्ति को शोकॉज़ नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। यह नोटिस कम-से-कम 15 दिन पहले भेजा जाना चाहिए, या जितना स्थानीय कानून अनुमति देता है, वह अवधि लागू होगी। नोटिस में स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण का कारण, उल्लंघन का विवरण और ध्वस्तीकरण के आधार बताए जाने चाहिए। नोटिस प्राप्त व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देना आवश्यक है। सुनवाई के बाद ही अंतिम ऑर्डर जारी किया जा सकता है और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को वीडियोग्राफ़ किया जाना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी दावे की समीक्षा की जा सके।

इधर इस मामले को लेकर बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर से यह कार्रवाई हुई है। स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त करने को लेकर एसडीएम एवं एसडीओपी से मेरी बात हुई थी, अवैध संरचना होने के कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए भवन को तोड़ने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। वहीं निजी भूमि पर स्कूल भवन बनाने वाले नईम भाई का कहना है कि 5 हजार वर्ग फीट पर डायवर्सन कर स्कूल भवन बनाने की अनुमति मांगी गई थी। सभी जगह आवेदन दिया गया है। कोई उल्लंघन हुआ है, तो मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं, मेरी विनती है कि स्कूल भवन नहीं तोड़ा जाए।

इधर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हेमंत वागद्रे ने कार्रवाई पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि इन गांवों के बच्चों को महाराष्ट्र पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए गांव के व्यक्ति ने निजी जमीन पर स्कूल तैयार किया था ताकि बच्चे शिक्षित हो सके, लेकिन इस तरह की कार्रवाई करना और भवन को तोड़ना गलत है अगर किसी नियम का पालन नहीं हुआ हो रहा है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर समय देकर उसका पालन कराया जा सकता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई गलत है।

पानी की शिकायत पर गांवों में पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष

आठनेर में ग्रामीणों के साथ बनाया पानी का पंचनामा

बैतूल। आठनेर विकासखंड के ग्राम टिपनापुर, खटगड़ और जावरा से मिल रही दूषित पेयजल की लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा संबंधित गांवों में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मौके पर दूषित पेयजल का पंचनामा तैयार कराया और पानी के सैंपल लिए। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी मूलभूत सुविधाओं, पेयजल संकट और स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव की जानकारी ली गई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आठनेर के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य पंकज वंजारे, लवलेश बब्बा राठौर, कमलेश कोसे, अशोक जितपुरे, राधे पटेल, बबलू बारस्कर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं माता-बहनें उपस्थित रहीं। कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को संगठन स्तर पर और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार 17 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कानूनी अधिकार को समाप्त करने के प्रस्ताव, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और प्रदेश में पानी की गुणवत्ता को लेकर व्यापक विरोध एवं संपर्क अभियान की कार्ययोजना बनाई गई है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 17 जनवरी को शहरी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा भागीरथपुरा इंदौर की घटना और पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों को लेकर जिला स्तर पर एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा, जबकि ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा मनरेगा, पानी की गुणवत्ता और भागीरथपुरा की घटना के विरोध में उपवास किया जाएगा।

कलेक्टर ने नगरपालिका बैतूल का किया औचक निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को नगरपालिका बैतूल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामान्य शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सामाजिक सुरक्षा शाखा, राजस्व शाखा, पीडब्ल्यूडी शाखा तथा जल प्रदाय शाखा सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कार्यालयीन समय में कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी ली एवं कार्य व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्यों के लिए नगरपालिका आए नागरिकों से चर्चा कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। इस अवसर पर नगर पालिका के प्रभारी अधीक्षक विजय हुद्दार, राजस्व शाखा के मदन विनोदकर समेत अन्य कर्म चारीगण उपस्थित थे।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्मा व नीना वर्मा समेत अनेक भाजपा नेता शामिल हुए

कार्यकाल के 1 बरस और जन्म दिन पर उत्सव और उल्लास

धार। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पद पर महंत निलेश भारती के 16 जनवरी को एक वर्ष पूर्ण होने व जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, विधायक नीना वर्मा ,पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार समेत हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर बधाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती जन्मदिन 16 जनवरी को सुबह 8 बजे रुद्राभिषेक सोमनाथ मठ सागौर में किया सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर सागौर में शामिल हुए वहा से लक्ष्मी गौशाला जेतपुरा धार में गौ माता का पूजन कर तिल गुड़ खिलाया। दोपहर 1

बजे श्रद्धालय वृद्धाश्रम धार में वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोपहर 2 बजे दीनदयाल रसोई केंद्र पहुंचकर भोजन सेवा में सहयोग किया तथा दोपहर 2 से 4 बजे तक भाजपा जिला कार्यालय धार में कार्यकर्ता द्वारा स्वागत समारोह के आयोजन में शामिल हुए । भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला कार्यालय पर जिले के सभी 18 मंडल अध्यक्षों व मंडल पदाधिकारी जिले के पदाधिकारी जिले के जनप्रतिनिधि गाना महिला मोर्चा की मातृशक्ति, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा सहित जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने और राकेश पटेल,कोषाध्यक्ष मोहित तातेड़ ने जिला अध्यक्ष महंत भारती को साफा पहनाकर पुष्पमाला से स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

प्राइवेट स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 जनवरी 2026

सीहोर (निप्र)। राज्य शिक्षा केन्द्र, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, किन्तु तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के तहत यदि कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उस स्कूल को मान्यता विहीन माना जाएगा और विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

आमसागर में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। ग्राम आम सागर में मंगलवार को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनिल कुमार द्विवेदी द्वारा सत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गांव में जन्मे बच्चों का गृह शिशु आधारित भेट भी किया गया व संस्थागत प्रसव ंउ के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विकासखंड कम्युनिटी मोबिलाइज श्री मुकेश कुमार बटाने, सीएचओ सुश्री सोनिका कुमरे, एएनएम श्रीमती सावित्री तिग्गा, आशा कार्यकर्ता सुश्री गुलाब इवने सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे।

सांसद खेल महोत्सव में जिले का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित

हरदा (निप्र)। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने सोमवार को नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारतीय राजू कमेड़िया, पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, जिला अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष टिमरनी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, पूर्व विधायक टिमरनी श्री संजय शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री संदीप पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व खिलाड़ी उपस्थित रहे। खेल समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन दिसंबर माह में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत एवं समूह खेल खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, एथेलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, योग, बैडमिंटन हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, पिट्ठू खेलों का आयोजन किया गया। संसदीय क्षेत्र बैतूल में आयोजित सभी खेलों में हरदा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से कबड्डी बालिका वर्ग, खो खो बालिका, फुटबाल बालिका वर्ग प्रथम स्थान, फुटबाल बालिका वर्ग, कुश्ती बालिका 50 किग्रा, रस्साकसी पुरुष प्रथम स्थान, कुश्ती 86 किग्रा पुरुष वर्ग, कुश्ती 85 किग्रा ग्राम पुरुष वर्ग, बैडमिंटन पुरुष वर्ग सिंगल्स एवं डबल्स, योग बालक वर्ग तथा एथेलेटिक्स 200 मीटर में प्रथम स्थान तथा हाकी पुरुष वर्ग तथा कुश्ती 65 किग्रा पुरुष में द्वितीय स्थान प्राप्त कर खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया।

9 माह में 33 बच्चों ने क्लब फुट विलनिक इस के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया

विदिशा (निप्र)। जिला चिकित्सालय विदिशा में संचालित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र (डीईआईसी) में जिले की समस्त आरबीएसके टीम चिकित्सालय की ओपीडी , एसएनसीयू, पीआईसीयू, एनआरसी प्रसूति वार्ड एवं अन्य शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सा संस्थाओं से आने वाले क्लबफुट की समस्या से ग्रसित शून्य से 18 वर्ष के बच्चों का उपचार जिला चिकित्सालय विदिशा में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के मार्गदर्शन में अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. गजेन्द्र सिंह दांगी एवं उनकी टीम के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को आरबीएसके कार्यक्रम अंतर्गत अनुष्का फाउंडेशन के सहयोग से क्लबफुट क्लीनिक का आयोजन किया जाता है। क्लबफुट एक ऐसी जन्मजात बीमारी है जिसके प्रभाव से बच्चे के जन्म से ही दोनों अथवा एक पैर के पंजे अंदर की और मुडे होते हैं जिसका इलाज सामान्यतः तीन चरणों में संपादित किया जाता है। प्रथम चरण में बच्चे के पैरों में कास्टिंग की जाती है, एक निश्चित अवधि के पश्चात दूसरे चरण में टीनोटामी की प्रक्रिया की जाती है ततपश्चात तीसरे चरण में बच्चे के पैर में ब्रेसेस पहनाये जाते हैं ताकि बच्चे के पैर सही अवस्था में आ जाएं।

ग्रामीण महिलाओं ने उड़ाई हौसलों की पतंग

समानता और आत्मनिर्भरता का दिया संदेश

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य कार्यालय भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में नई चेतना 4.0 - जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 'एक साथ एक आवाज, समानता के लिए हौसलों की उड़ान' विषय पर बुधवार को मां नर्मदा के पावन तट स्थित पोस्ट ऑफिस घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर तिल-गुड़ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मिलकर तिल-गुड़ के लड्डू खाए और अपने स्वतंत्र विचार साझा किए। महिलाओं ने हौसलों की पतंग उड़ाकर अपनी आकांक्षाओं और अधूरे सपनों को पतंगों पर संदेश के रूप में लिखते हुए उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान देश की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि सावित्रीबाई फुले ने पुणे (महाराष्ट्र) में प्रथम तिल-गुड़ सभा का आयोजन

कर महिलाओं को समानता, संगठन और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया था। साथ ही तिल और गुड़ के पोषण संबंधी महत्व की जानकारी दी गई, जिसमें तिल को प्रोटीन व पोषक तत्वों से भरपूर तथा गुड़ को आयरन का प्रमुख स्रोत बताया गया, जो एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाव में सहायक है। आजीविका मिशन द्वारा 13 से 15 जनवरी तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 13 जनवरी को लखपति दीदी संवाद के माध्यम से उन महिलाओं ने अपनी प्रेरणादायी गाथाएं साझा कीं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। 14 जनवरी को जिले के समस्त विकासखंडों में विशेष पतंग महोत्सव एवं तिल-गुड़ बैठकें आयोजित की गईं। वहीं 15 जनवरी को सभी सात विकासखंडों में चिकित्सा विभाग के सहयोग से महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। विकासखंड नर्मदापुरम का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर डोलरिया स्थित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य कार्यालय भोपाल से श्री सनी सिंह, जिला कार्यालय से आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक रोजगार एवं कौशल उन्नयन श्रीमती अर्चना शुक्ला रूसिया, विकासखंड नर्मदापुरम से विकासखंड प्रबंधक श्री दुर्गेश ठाकुर, सहायक विकासखंड प्रबंधक श्री राजन केरकेट्टा, श्रीमती कविता पाठक, श्रीमती नीरज सिंह परिहार, श्री हिमांशु पवार, श्री पवन मानकर सहित स्व सहायता समूहों की महिलाएं एवं आर-सेटी में रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही ग्रामीण युवतियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में समानता, आत्मविश्वास, संगठन और आत्मनिर्भरता का सशक्त संदेश दिया गया।

लापरवाही पर सीएचओ और एएनएम के विरुद्ध होगी कार्यवाही

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें गर्भवती माताओं की जांच एवं हाई रिक्स गर्भवती महिलाओं की चिन्हांकन एवं प्रबंधन में कम उपलब्धि पाई गई। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे ने गर्भवती महिलाओं की जांच, हाई रिक्स चिन्हांकन एवं प्रबंधन में लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पर तीन सीएचओ मोनिका भूमरकर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बोदी जूनामानी, ज्योति धोटे हेल्थ एण्ड बेलनेस सेंटर डेढ़पानी, संतोष बडकुले हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर चांदू रातामाटी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की। साथ ही डॉ.हुरमाड़े द्वारा सात सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा तीन एएनएम-श्रीमती संध्या कालभोर, श्रीमती उर्मिला इवने, श्रीमती गीता रघुवंशी को गर्भवती महिलाओं के पंजीयन समय पर नहीं करने, कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर दो-दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही एवं तीन एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने भोजपुर शिव मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा बुधवार को भोजपुर स्थित विश्वप्रसिद्ध शिव मंदिर पहुंचकर मकर सक्रांति पर्व के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार तथा एसडीएम श्री चन्द्रशेखर श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

जलियांवाला बाग की तरह पावन है सीहोर का शहीद स्थल, 356 क्रांतिकारियों ने दिया था अपने प्राणों का बलिदान

100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हुआ ध्वजारोहण

सीहोर (निप्र)। सीहोर के सैकड़ाखेड़ी स्थित शहीद स्थल पर शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, कलेक्टर श्री बालागुरू के. एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने शहीद स्थल पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वारोहण किया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। इस अवसर पर विधायक श्री राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, पंडित प्रदीप मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने कहा कि आज का दिन सीहोर के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 1858 को सीहोर में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में 356 क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रहे विद्रोह में सीहोर की बर्बरतापूर्ण घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। उन्होंने कहा कि सीहोर का यह स्थल हम सबके लिए पवित्र स्थान है। उन्होंने कहा कि उन सभी अमर शहीदों की शहादत को अमर बनाए रखने के लिए इस स्थल का निरंतर समग्र विकास किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. और एसपी श्री शुक्ला ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जिस प्रकार जलियांवाला बाग देश की स्वतंत्रता में शहीदों द्वारा दिए गए प्राणों के बलिदान की गवाही देता है, उसी प्रकार नागरिकों के लिए सीहोर का यह अमर शहीद स्थल प्रेरणा और गरिमा का स्त्रोत है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुती देने वाले सभी 356 क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कहा कि यह क्रांती हिंदू-मुस्लिम एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस क्रांति मे शामिल क्रांतिकारियों का यह मानना था कि सबसे पहले हमारा देश है, देश से बढ़कर कुछ नही है। हमारे इन वीर क्रांतिकारियों से हमे प्रेरणा लेनी चाहिए एवं देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में विधायक श्री राय, भाजपा अध्यक्ष श्री मेवाड़ा, पंडित मिश्रा, नपा अध्यक्ष श्री राठौर, कलेक्टर श्री बालागुरू के. और एसपी श्री शुक्ला ने नगर पालिका के नवीन टोइंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना है। इस अवसर सभी ने मकर सक्रांती के उपलक्ष्य में पंतग उड़ाकर पतंग महोत्सव का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संगीतिका संगीत महाविद्यालय की टीम द्वारा अनेक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य श्री सीताराम यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जसपाल अरोरा, श्री राजकुमार गुप्ता, श्री पंकज गुप्ता, श्री सुदीप प्रजापति, श्री सुरेंद्र मेवाड़ा, श्री आनंद गांधी, श्री राजीव गुजराती सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और स्कूली बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजली दी।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने लेडी भोर शहरी स्वास्थ्य केंद्र भोपाल के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया।

16 साल की बच्ची को होमगार्ड के जवानों ने डूबने से बचाया

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले की लटेरी तहसील के मुरवास के बड़ी मदागन कुंड में आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे, इसी दौरान एक 16 साल की बच्ची कुंड में नहाने के दौरान डूब रही थी, जिसे मौके पर तैनात होमगार्ड जवानों की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर एक बच्ची पूजा अहिरवार पुत्री बुंदेल सिंह उम्र 16 साल निवासी खलीलपुर थाना मुरवास बड़ी मदागन कुंड में नहाने के दौरान डूब गई थी। जिसे मौके पर तैनात होमगार्ड तैराक टीम लटेरी द्वारा सुरक्षित निकाल कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है, अब बच्ची सकुशल है।

धरती आबा अभियान के विशेष शिविरों ने बदली सहरिया परिवारों की उम्मीदें

विदिशा (निप्र)। धरती आबा अभियान के अंतर्गत जिले के चिन्हित ग्रामों में विशेष शिविरों का आयोजन कर शासन की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में बासौदा तहसील के ग्राम काचरोध एवं दाऊद बासौदा में एक साथ विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य जनजातीय परिवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र त्वरित रूप से उपलब्ध कराना रहा। तहसीलदार श्री अरविन्द यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों के माध्यम से दोनों ग्रामों के कुल 81 हितग्राहियों को मौके पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर प्रदान किए गए। इनमें दाऊद बासौदा के 60 एवं ग्राम काचरोध के 21 हितग्राही शामिल हैं। शिविर में सभी प्रक्रियाएं सरल एवं पारदर्शी रखी गई, जिससे ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

ग्राम काचरोध निवासी श्री राजेश सहरिया, पिता मुन्ना लाल सहरिया ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जाति प्रमाण पत्र घर बैठे ही मिल जाएगा। उन्होंने इस सुविधा के लिए शासन एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया। धरती आबा अभियान के अंतर्गत आयोजित ये विशेष शिविर प्रशासन की संवेदनशीलता एवं जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे जनजातीय एवं वंचित वर्गों को समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो रहे हैं और वे विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त कर पा रहे हैं।

शमशाबाद में गणतंत्र दिवस आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने की बैठक

विदिशा (निप्र)। शमशाबाद अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह पटेल ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के संबंध में शमशाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। एसडीएम श्री पटेल ने बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी विभागों को उनकी-उनकी जिम्मेदारियां सौंपीं। उन्होंने ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा, यातायात एवं चिकित्सा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों के सम्मान में सम्मलेन का किया गया आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस' के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों के सम्मान में सैनिक सम्मलेन का आयोजन जिला कलेक्टर कार्यालय के 'रेवा सभा कक्ष' में किया गया। जिसमे जिले की सभी तहसीलों के पूर्व सैनिक, वीर नारियाँ एवं उनके आश्रित शामिल हुए। सम्मलेन का शुभारम्भ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईकृष्णा एस. थोटा एवं ए डी एम नर्मदापुरम श्री राजीव रंजन पांडेय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के पश्चात शहीदों की याद में 2 मिनिट का मौन धारण किया गया। तत्पश्चात सम्मलेन में उपस्थित सभी लोगो ने सम्लित रूप

से राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा वीर नारियों को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बलों के दिग्गजों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो देश की सेवा और सुरक्षा के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करता है, जिसमें उनके परिवारों (वीर नारियों) के बलिदान को भी सराहा जाता है और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं व जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। मुख्य अतिथि ने बताया कि यह दिन देश की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले, और युद्धों व आपात स्थितियों में सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सभी पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों (वीर नारियों) और विकलांग सैनिकों के योगदान को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। पूर्व सैनिक देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करते हैं। यह दिन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पूर्व सैनिकों के प्रति राष्ट्र के गहरे सम्मान और आत्मीयता को दर्शाता है, और उनसे जुड़े सामाजिक और कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने पूर्व सैनिको का हमेशा सम्मान करना चाहिए एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आदर्शों को अपनाना चाहिए।

पूर्व सैनिकों ने मनाया 10वां सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस

बैतूल (निप्र)। 10वां सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बैतूल में 14 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट द्वारा वीर नारियों, वीर महिलाओं एवं वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिक दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सीमा की रक्षा के लिये अदम्य साहस, समर्पण, बलिदान और देशभक्ति के साथ निस्वार्थ सेवा करने वाले सशस्त्र बलों के सेवानिवृत सैनिकों के प्रति हमारा सदैव आभार रहेगा। इस अवसर पर कैप्टन भारतीय नौसेना श्री सुमीत सिंह (से.नि.), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा 140 पूर्व सैनिकों को उनके द्वारा देश के लिए दिये गए सम्मानजनक योगदान के लिए प्रशासन द्वारा जारी किया प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

भोपाल में की घोषणाएं, 62 वर्ष में होगा रिटायरमेंट, संविलियन के लिए बनेगी कमेटी

ग्रामीण विकास में पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में वास करती है। महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा- अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो गांव, किसान और गरीब की प्रगति पर ध्यान देना होगा, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर देश का विकास करना है तो गांवों को विकसित करें, देश अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचलों में उद्योग स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव ही स्वावलंबी भारत की नींव हैं। राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों की समृद्धि और ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष-2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसमें 16 अलग-अलग विभागों को शामिल किया गया है। कृषि कल्याण वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु-कुटीर उद्योग सहित सभी विभागों की योजनाओं का लाभ पंचायत हितग्राहियों को मिलेगा। ग्रामीण विकास में पंचायत सचिवों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को भेल दशहरा मैदान पर आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के हाथों में काम देकर उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे कारखाने और उद्योग लगेंगे तो देश स्वतः प्रगति करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसान इन चार वर्गों को केंद्र में रखकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम किया जा रहा है।

सीएम की बड़ी घोषणाएं

- पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 वर्ष होगी।
- 13 सितंबर 2023 से सातवें वेतनमान के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
- पंचायत सचिवों को 1300 का विशेष भत्ता दिया जाएगा।
- सचिव की मृत्यु के बाद डेढ़ लाख रुपए की अनुग्रह राशि दस किश्तों में वापस लेने का नियम समाप्त किया जाएगा, अब यह राशि वापस नहीं ली जाएगी।
- संविलियन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसके परिणाम जल्द आएंगे।

2026 कृषि कल्याण वर्ष, पंचायत सचिवों की भूमिका अहम- मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 16 विभागों को जोड़ा गया है। इन सभी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया में डरावने हालात दिखते हों, लेकिन गांवों ने कोविड काल से लेकर अब तक हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है।

गांवों को और अधिकार, बेहतर ढांचा- मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन गांव योजना के तहत गांवों का विकास किया जा रहा है। सरपंचों को जहां 25 लाख रुपए तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है, वहीं पंचायत सचिवों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, अटल भवन, सामुदायिक भवन और पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जहां बुलाओगे, वहां आऊंगा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा,सरकार के अभी तीन साल हैं। बार-बार आना-जाना होगा। आप जहां बुलाओगे, मैं वहां आ जाऊंगा।

पंचायत सचिव, सरकार और जनता के बीच सेतु

प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने कहा कि यह सम्मेलन मात्र औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किए जाने के संकल्प में पंचायत सचिवों की भूमिका केंद्रीय है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासनकाल में 509 रुपए मानदेय पर काम करने वाले सचिवों को आज भाजपा सरकार ने सम्मान दिया है।

राजेश पटेल ने प्रमुख मांगें रखते हुए कहा 23 हजार पंचायतों में केवल 18 हजार सचिव कार्यरत हैं। समयमान वेतनमान, अनुकम्पा नियुक्ति और ओबीसी रोस्टर के कारण समस्याएं बनी हुई हैं। हम दूसरों के आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, हमारे परिवारों के भी आयुष्मान कार्ड बनें। सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी कर्मचारियों की तरह दिए जाएं। सचिव की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए और वह वापस न ली जाए।

कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान

भारतीय मजदूर संघ के कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर निर्णय न लिया हो। वर्षों से लंबित कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हुआ है। सभी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और सरकार के संकल्पों को पूरा करने के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं।

पंचायत सचिव हैं पंचायत व्यवस्था की आत्मा

सीएम ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे मजबूत इकाई पंचायत है और उसकी आत्मा पंचायत सचिव हैं। चाहे कितना ही बड़ा आईएएसअधिकारी क्यों न हो, प्रधानमंत्री या राज्य सरकार का निर्णय–सबका वास्तविक क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर ही होता है। उन्होंने कहा, भगवान राम के समय जो असंभव कार्य हनुमान जी करते थे, आज वही काम हमारे पंचायत सचिव करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल गंगा अभियान, हर घर जल योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत सचिवों के माध्यम से ही होता है। कई बार लोग अपने परिवार से अधिक भरोसा पंचायत सचिव पर करते हैं और उन्हें अपने सुख-दुख का सहभागी मानते हैं।

राहुल गांधी आज इंदौर में, बॉम्बे हॉस्पिटल व भागीरथपुरा जाएंगे

साढ़े 3 घंटे का दौरा, कितने परिजनों से मिलेंगे तय नहीं

इंदौर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर दौरा तय हो गया। वे शनिवार को सुबह 11 बजे विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे। विमानतल पर उनकी अगवानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रभारी हरीश चौधरी, सहप्रभारी उषा नायडू, चिंटू चौकसे, विपिन वानखेड़े सहित अन्य करेंगे।

राहुल गांधी 15 मिनट बाद 11.15 बजे विमानतल से बाम्बे अस्पताल के लिए रवाना होंगे। यहां वे करीब आधा घंटा भागीरथपुरा दूषित जल पीने से बीमार हुए भर्ती लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके हालचाल जानेंगे। करीब 12.15 बजे राहुल गांधी बाम्बे अस्पताल से रवाना होकर 12.45 पर भागीरथपुरा पहुंचेंगे। यहां वे करीब एक घंटा रुकेंगे। कांग्रेस सूची बना रही है कि उनके साथ में कौन रहेगा। वे भागीरथपुरा रुकेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। करीब 1.45 बजे राहुल गांधी भागीरथपुरा से रवाना होकर इंदौर विमानतल पहुंचेंगे, जहां से वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने प्रदेश भर के पार्षदों को लेकर सम्मेलन का आयोजन भी रखा था, लेकिन उसकी स्वीकृति प्रशासनिक रूप से नहीं मिली। इसलिए अब केवल पीड़ितों से ही राहुल गांधी मिलेंगे और इंदौर में ही करीब साढ़े तीन घंटा रूकेंगे। अभी यह तय नहीं हुआ कि राहुल गांधी सभी 24 मृतकों से मिलेंगे या उसमें भी चयन किया गया है।

दिल्ली से राहुल गांधी के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा भागीरथपुरा पहुंचे। गुरुवार दोपहर दिल्ली से राहुल गांधी के दफ्तर के प्रतिनिधि ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ क्षेत्र का दौरा किया। किन-किन घरों में मौतें हुई, इस बारे में जानकारी ली। इसके बाद मृतकों के नाम-पते की सूची कांग्रेस की ओर से इंदौर प्रशासन को देकर उनके घर राहुल गांधी को मिलाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन, प्रशासन के अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से कहा गया कि क्षेत्र की संकरी गलियों में राहुल गांधी की सुरक्षा टीम और गाड़ियों का जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में सभी मृतकों के घर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मृतक के परिजनों को चेक- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा में मृत हुए 24 लोगों के लिए 1-1 लाख रु. के चेक देने का ऐलान किया है। इन मृतकों की सूची तैयार की जा रही है और उनके परिजनों से पूछा जाएगा कि प्रदेश कांग्रेस जो चेक बना रही है वह किस नाम से बनेगा। चेक भोपाल से बनकर इंदौर पहुंच जाएंगे।

बसंत पंचमी पर भोजशाला में नमाज तो होगी, संख्या कम होने का भरोसा

इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार पठान ने मीडिया से चर्चा की

धार। बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार है और उस दिन भी मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में स्थित कमाल मौला मस्जिद में ही जुमे की नमाज अदा करेगा। इस बात की जानकारी कमाल मौला मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार पठान ने दी। जुमे की नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस दिन नमाज पढ़ने वालों की संख्या कम कर सकते हैं, पर नमाज तो यहीं होगी।

जुल्फिकार पठान ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनी है और आगे भी यह व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन, जुमे की नमाज मुस्लिम समाज का संवैधानिक अधिकार है। 1935 में भी इस बात को कंटिन्यू किया गया और बताया कि यह कमाल मौला मस्जिद है। जैसे इसमें आज नमाज हुई, वैसे आगे भी नमाज होती रहेगी। 1952 में भी इस चीज को कंटिन्यू किया और 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है उसमें भी आर्कियोलॉजिकल विभाग ने इस बात को कायम रखा है। अभी जो शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी कलेक्टर और एसपी ने बताया कि केंद्र का एक आदेश आना बाकी है, हम उस आदेश का पूरी तरह का पालन करेंगे।

उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जहां तक परंपरा की बात है, तो वह भी मायने रखती है। लेकिन, शहर की शांति के लिए मुस्लिम समाज सहयोग कर रहा है और आगे भी सहयोग करेगा। शहर में शांति के लिए मुस्लिम समाज त्याग करने को तैयार है। अभी मुस्लिम समाज जिस तादाद में नमाज पढ़ता है, हम वह तादाद कम

कर सकते हैं। यह सब शांति के लिए ही होगा। मुस्लिम समाज का संवैधानिक अधिकार है और इस स्थान को हम कमाल मौला मस्जिद ही मानते हैं। जुमे की नमाज यही होगी। क्योंकि, यहां 800 साल से नमाज होती रही है और हम चाहते हैं कि शहर में शांति रहे और मुस्लिम समाज भी शांति व्यवस्था में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा और यहां शांति बनी रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक कौमी एकता की बात है तो यह मिसाल की बात है, तो यह तब होगा जब यहां दोनों आयोजन शांति के साथ हों। 2006, 2013 और 2016 में भी यहां पर शांतिपूर्वक नमाज हुई थी। हम शांति व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे और हमारी पुलिस भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास कर रही हैं। मुस्लिम समाज भी शांति के लिए लगा है और 100त्न शांति रहेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आदेश आएगा, उसका भी पालन होगा और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी।

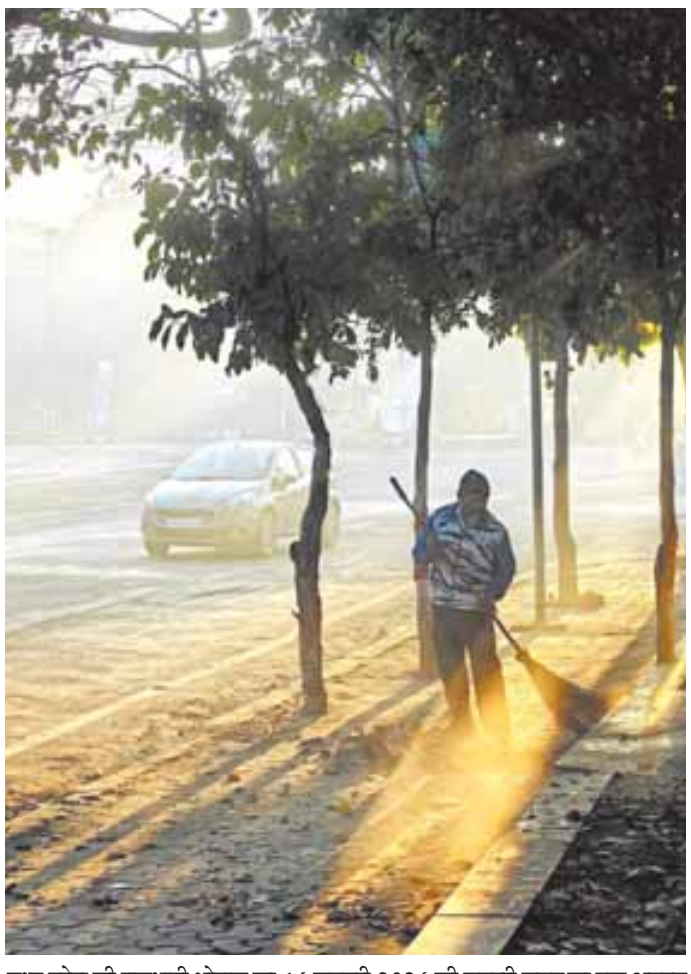

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का 16 जनवरी 2026 की सुनहरी सुबह का एक अनुपम दृश्य जिसमें नगर निगम का एक समर्पित कर्मचारी भोपाल शहर को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। **– छायांकन : जगदीश कौशल, भोपाल**

प्लेन में हार्ट अटैक तो मशीन देगी ट्रीटमेंट

एम्स की भूलभुलैया में रास्ते दिखाएगा नेविगेशन, एमपी के सरकारी सिस्टम में एआई का उपयोग होगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजन बिल्डिंग के अंदर की भूलभुलैया में भटकते रहते हैं। पैथोलॉजी कहां पर है, एमआरआई कहां होगी, किस विभाग के डॉक्टर कहां बैठते हैं? ये जानकारी बार-बार पूछने में वक्त बर्बाद नहीं होगा।

गूगल मैप की तरह एम्स की बिल्डिंग का पूरा नेविगेशन आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए मरीजों उनके परिजनों और विजिटर्स के लिए मददगार साबित होगा। भोपाल के एक स्टार्टअप ने ये नेविगेशन तैयार किया है। एम्स के मोबाइल एप और बारकोड को स्कैन करने के बाद व्यक्ति को एम्स में जिस जगह जाना है उसे सर्च करते ही एआई नेविगेशन रास्ता दिखाएगा। अकेले यही नहीं मप्र सरकार एआई की मदद से सरकारी सिस्टम में कई बड़े प्रयास कर रही है।

भोपाल के होटल ताज में रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस में ऐसे कई नवाचार देखने को मिले जो सरकारी सिस्टम के साथ आम आदमी को मदद कर रहे हैं।

रोबोट से 10 हजार स्क्वायर फीट की सफाई

सी-1 क्लीनिंग रोबोट: इंदौर की फ्बिरोबोटिक्स के रोहिताश दुबे ने बताया ये रोबोट झाड़ू, पौंछा और स्क्रबिंग तीनों काम करता है। एक घंटे में 10 हजार स्क्वायर फीट के एरिया को क्लीन कर सकता है। ये रोबोट 100 प्रतिशत ऑटोनॉमस है। एक बार रोबोट को जगह मैप करा दीजिए उसमें टाइम सेट कर दीजिए कि कितने बजे सफाई करानी है उतने बजे से रोबोट अपने आप मैप किए गए एरिया की क्लीनिंग कर सकता है। इसका उपयोग अस्पतालों, होटलों और बड़े दफ्तरों में किया जा रहा है।

आउटडोर लॉजिस्टिक्स रोबोट: ये आउटडोर लॉजिस्टिक्स रोबोट है जो 500 किलो वजन का सामान पहुंचा सकता है। इंदौर में इस रोबोट की टेस्टिंग हो चुकी है। अब यह रोबोट यूएस के साउथ कैरोलीना मर्टल बीच सिटी में कुछ एप्लिकेशन के लिए इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि मैनुअल लेबर वर्क को कम किया जा सके।

एआई सिखाता है बोलने का तरीका, फेसबुक ने की फंडिंग

कॉमन स्कूल का स्टार्टअप चलाने वाले कृष्णकांत ने बताया कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पर एआई रोल प्ले के माध्यम से ट्रेंड करते हैं। अब तक हम लोग 40 हजार लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। ग्वालियर में बैठकर हम लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इसे फेसबुक ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी और एचडीएफसी बैंक ने इस प्लेटफार्म को फंडिंग और सपोर्ट किया हुआ है।

फसल में बीमारियों का अलर्ट बताता है एग्रीदूत

एग्रीदूत, एग्रीटेक स्टार्टअप के को-फाउंडर मृदुल श्रीवास्तव ने बताया हम लोग खेती में एआई, सैटेलाइट और डिवाइस की मदद से तकनीक को जोड़ रहे हैं। खेत में कब कौन सी बीमारी आने वाली है। कब मौसम बदलेगा? सिंचाई कब करनी है? ये जानकारी मिलती है। सैटेलाइट की मदद से मिट्टी में जैविक कार्बन की स्थिति पता चलती है, नमी का स्तर कैसा है? खेत में फसल कहां खराब हो रही है कहां अच्छी है। पूरा अलर्ट एप पर मिलता है।

अगर कोई बीमारी फसल में फैल गई तो उसे पहचानने के लिए एप पर पत्ती की फोटो स्कैन करके देख सकते हैं। ये भोपाल बेस्ड स्टार्ट अप है। अब तक 30 हजार किसानों को फायदा पहुंचाया है। अब तक जो किसान अंदाजे से खेती कर रहा था अब वो एप आधारित और एआई की मदद से हो रही है। इससे क्वालिटी बढ़ रही है। किसानों की समझ बढ़ रही है कि कम खाद में कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हैं।

दिव्यांग युवती के प्लॉट का न विकास न मिला कब्जा

13 साल बाद इंसाफ, आयोग ने बीडीए को कब्जा या ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए

भोपाल (नप्र)। भोपाल की आवासीय योजनाओं में देरी और अधूरे विकास को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। इसी कड़ी में जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर सिटी आवासीय योजना से जुड़े एक मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

आयोग ने माना कि वर्षों तक भूखंड का विकास कार्य पूरा नहीं करना और कब्जा नहीं देना उपभोक्ता के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। आयोग ने इस मामले में कब्जा देने के साथ-साथ मुआवजे और ब्याज सहित राशि लौटाने का भी विकल्प दिया है।

क्या है पूरा मामला

एयर सिटी आवासीय योजना से जुड़ा यह मामला वर्ष 2013 से चला आ रहा है। योजना के विज्ञापन से प्रभावित होकर एक दिव्यांग युवती के परिजन ने भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसके नाम पर आवासीय भूखंड बुक कराया था। 29 जनवरी 2013 को भूखंड का पंजीयन कराया गया और इसके बाद किस्तों में कुल करीब 9.07 लाख रुपए की राशि भोपाल विकास प्राधिकरण को जमा कर दी गई। बीडीए द्वारा भूखंड का आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन तय समय-सीमा बीतने के बाद भी न तो योजना का विकास पूरा किया गया और न ही भूखंड का कब्जा या रजिस्ट्री कराई गई। वर्षों तक इंतजार और बार-बार संपर्क के बावजूद स्थिति साफ न होने पर आखिरकार परिजन ने 16 फरवरी 2018 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग की सुनवाई और टिप्पणी- सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि भुगतान लेने के बाद भी वर्षों तक विकास कार्य अधूरा रखना सेवा में गंभीर कमी है। आयोग ने यह भी कहा कि बीडीए यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि योजना का विकास कब तक पूरा होगा। बीडीए की ओर से यह दलील दी गई कि शिकायत समय-सीमा के बाहर है, लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जब तक उपभोक्ता को भूखंड का कब्जा नहीं दिया जाता।

नग्न हालत में भागते महिला-युवक का वीडियो हुआ वायरल

सागर में दोस्त की मां से दुष्कर्म का आरोप, एफआईआर के बाद आरोपी का शव फंदे पर लटका मिला

सागर (नप्र)। सागर जिले में एक महिला और युवक का नग्न अवस्था में सड़क पर भागते हुए वीडियो सामने आया है। दूसरा वीडियो भी है, जिसमें महिला अकेली बिना कपड़े पहने सड़क पर चल रही है। शुक्रवार को यह वीडियो बेटे के दोस्त पर दर्ज दुष्कर्म मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी की रात, महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पीड़िता ने 12 जनवरी को मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप है कि महिला के बेटे का दोस्त हीरालाल देर रात घर में घुसा और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया।

आरोपी के परिजनों ने किया चक्काजाम- कुछ समय बाद आरोपी का शव बांदरी थाना क्षेत्र के खेत में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर मर्ग कायम किया। शुक्रवार को आरोपी के परिजनों ने मोतीनगर चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम किया और आरोप लगाया कि

उनके खिलाफ झूठा दुष्कर्म मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

पुलिस ने कहा- वीडियो की जांच जारी- गुरुवार रात सामने आए दो वीडियो में पहला वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें महिला नग्न अवस्था में घर से बाहर भागती दिखाई दे रही है, और उसके ठीक पीछे युवक अर्धनग्न हालत में हाथ में जूते लिए दूसरी दिशा में भागता नजर आता है। दूसरे वीडियो में महिला अकेली नग्न अवस्था में सड़क पर चल रही है। पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच जारी है और फिलहाल इसके मामले से सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

एएसपी बोले- आरोपी पर दुष्कर्म का केस था दर्ज- एडिशनल एसपी लोकेश सिंहा ने बताया कि महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने सुसाइड कर लिया। बांदरी थाना में मर्ग कायम किया गया है। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। जिसमें प्रमाणित हुआ है कि आरोपी द्वारा महिला से दुष्कर्म किया गया था।